www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 34 | गोरखपुर, 9 मार्च 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता : मोदी

नवसारी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए कानूनों में संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानून (भारतीय दंड संहिता) का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया है तथा इससे शिकायत दर्ज कराने में आसानी और न्याय प्रदान करने में तेजी आई है। मोदी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नवसारी जिले के वांसी बोरसी गांव में एक जनसभा में कहा कि भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा, जब कोई लड़की देर से घर लौटती है, तो उसके माता-पिता सवाल पूछते हैं, लेकिन जब कोई लड़का देर से आता है, तो वे ऐसा नहीं करते, उन्हें ऐसा करना चाहिए। पिछले दशक में, हमने महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए हमने सख्त नियम और कानून बनाए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरी सरकार ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए कानून में बदलाव किया। महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित की हैं। मोदी ने कहा कि देश भर में लगभग 800 अदालत स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से अधिकतर अब कार्यरत हैं। हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सुविधा को सर्वोच्च महत्व देती है।

उन्होंने कहा, नई लागू की गई भारतीय न्याय संहिता ने औपनिवेशिक कानून को खत्म कर दिया है तथा महिला सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को और मजबूत किया है। नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए इसमें एक अलग अध्याय जोड़ा गया है।

पीड़ितों को पहले न्याय में देरी की शिकायत होती थी, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए नए कानून में बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में 60 दिन के भीतर आरोप तय करने और 45 दिन के भीतर फैसला सुनाए जाने का प्रावधान किया गया है। नए कानून में कहीं से भी ई-प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी गई है, जिससे पुलिस के लिए तत्काल कार्रवाई करना आसान हो गया है।

मोदी ने कहा कि ह्यजीरोह्ण प्राथमिकी के प्रावधान के तहत कोई भी महिला अत्याचार का सामना करने पर किसी भी थाने में मामला दर्ज करा सकती है। पुलिस अब बलात्कार पीड़िताओं के बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज कर सकती है, जिसे कानूनी मान्यता मिल गई है।

मोदी ने कहा, डॉक्टरों के मेडिकल रिपोर्ट भेजने के लिए सात दिन की समयसीमा तय की गई है, जिससे पीड़िताओं को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। बीएनएस में नए प्रावधानों के पहले से ही परिणाम दिखने की बात रेखांकित करते हुए मोदी ने याद दिलाया कि सूरत में सामूहिक बलात्कार के एक मामले में घटना के 15 दिन के भीतर आरोप तय कर दिए गए और दोषियों को कुछ ही हफ्तों के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई।

मोदी ने कहा कि महिलाओं का आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा कवच है। मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूं। मेरे बयान से कुछ को परेशानी हो सकती है। लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हूं पैसों के मामले में नहीं, बल्कि करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के आशीर्वाद के कारण। ये आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत, पूंजी और सुरक्षा कवच हैं।

उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना समाज और राष्ट्र के विकास की दिशा में पहला कदम है।

मोदी ने कहा कि भारत अब देश की तीव्र प्रगति के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पथ पर चल रहा है। हमारी सरकार महिलाओं के सम्मान और सुविधा को सर्वोच्च महत्व देती है। हमने हजारों शौचालय बनवाए और महिलाओं को सम्मान दिया। हमारी सरकार ने ह्यतीन तलाकह्ण के खिलाफ कड़ा कानून बनाया और लाखों मुस्लिम महिलाओं का जीवन बर्बाद होने से बचाया। हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों और अवसरों को प्राथमिकता दी है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि देश की आत्मा गांवों में बसती है। मैं इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि महिलाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की आत्मा हैं और ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण में बसती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसकी आर्थिक प्रगति की नींव लाखों महिलाओं ने रखी है और इस उपलब्धि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उन्होंने कहा, देश भर में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) संचालित कर रही हैं, जिनमें से तीन लाख से अधिक एसएचजी अकेले गुजरात में संचालित हैं। सरकार इन लाखों महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका लक्ष्य उन्हें ह्यलखपति दीदी बनाना है। लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं पहले ही लखपति दीदीह्ण बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है।

लखपति दीदी योजना केंद्र सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई थी। इसमें स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में मान्यता दी गई थी, जिनकी कृषि, पशुपालन और छोटे उद्योगों से वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपए है।

महिला दिवसः एक दिन नहीं, रोज करें महिलाओं का सम्मान

वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर नमामि गंगे ने विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए संदेश दिया कि महिलाओं का सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन होना चाहिए। उन्होंने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में भारत मां की आरती उतारी और महिलाओं के समान अवसर, नेतृत्व, सुखद समन्वय और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल एक सामाजिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक प्रगतिशील समाज की पहचान भी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए देश की महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। इस मौके पर पूजा मौर्या, बेबी तिवारी, शालिनी दीक्षित, राधा शर्मा, सूर्यांशु शुक्ला आदि रहे।

गन्ने की तौल बंद होने पर किसानों ने शुरू किया धरना

अलीगढ़। जट्टारी-पिसावा मार्ग के चौड़ीकरण कार्य के चलते गन्ने की तौल बंद होने पर किसान धरने पर बैठ गए। तहसीलदार गभाना उदयवीर सिंह ने पहुंचकर तौल शुरू कराई तब धरना समाप्त हुआ। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर गन्ना किसानों के हित में निर्माण कार्य रोके जाने की मांग की। साथ ही ठेकेदार द्वारा सड़क के साइड से खोदी गई मिट्टी को बेचे जाने, गन्ना क्रय केंद्र चालू कराने, भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की पार्किंग को खाली कराने, मानक के अनुरूप सड़क निर्माण कराने, सड़क किनारे नाली निर्माण और अतिक्रमण हटवाए जाने की मांग की। तहसीलदार ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से अतिक्रमण हटवाए जाने के लिए कहा। लोक निर्माण विभाग के एई रजनीश कुमार ने बताया कि आपत्ति वाले स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर सड़क निर्माण जारी रहेगा।

सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जलेगी होलिका

गोरखपुर। होली के दिन जुलूस वाले प्रमुख रास्तों पर ड्रोन उड़ाकर अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। संवेदनशील स्थानों और होलिका दहन वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। जहां भी पुराने कैमरे लगे हैं, सत्यापन कर उनकी मरम्मत कराई जाए ताकि कंट्रोल रूम से सभी स्थानों की निगरानी की जा सके। थाना स्तर पर प्रस्तावित हिस्ट्रीशीटर और होली में हुड़दंग करने वाले अराजक तत्वों पर भी कार्रवाई की जाए। होली और ईद को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में शुक्रवार को आयोजित गोष्ठी में एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने ये आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एसपी सिटी, एसपी साउथ, एसपी नार्थ, सभी सीओ और थानेदार मौजूद रहे। सभी सीओ व थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि होलिका दहन आयोजकों, जुलूस व मसान होली के आयोजकों, डीजे संचालकों और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की मीटिंग की जाए। होलिका दहन वाले स्थान के नोडल नियुक्त किए जाएं। सभी नोडल अधिकारी संवेदनशील स्थानों व होलिका दहन के स्थानों का भौतिक सत्यापन करें।

'ब्रांड बेंगलुरु' के लिए एक अच्छा बजट : शिवकुमार

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को राज्य के बजट को देश के लिए एक मॉडल बताते हुए कहा कि इसमें बेंगलुरु की यातायात समस्याओं के समाधान के लिए कई परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है।

बेंगलुरु विकास के प्रभारी मंत्री शिवकुमार ने कहा कि शहर में 700-800 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी जा रही हैं। शिवकुमार ने कहा, ह्यहम बजट देश के लिए एक आदर्श है। अन्य राज्य भी इस पर ध्यान देंगे। यह ब्रांड बेंगलुरु के लिए एक अच्छा बजट है। बजट शहर की 1.40 करोड़ आबादी के हित में है। इसमें एक सुरंग सड़क परियोजना भी है।

पत्रकारवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यातायात की समस्याओं को दूर करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा, डबल-डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे और नगर निगम और बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) से 50-50 प्रतिशत योगदान के साथ नई मेट्रो परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

उपमुख्यमंत्री ने कहा, सुरंग सड़कों सहित हम 700-800 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ रहे हैं। हम ऋण ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को राहत देना चाहते हैं। गत दिनों शुक्रवार को विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सरकार बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारा (सुरंग) परियोजनाओं के लिए 19हजार करोड़ रुपए की राशि के लिए गारंटर के रूप में खड़ी है, जिसकी लागत 40हजार करोड़ रुपए होगी।

बाबा साहब के विचारों और उनकी सोच का अपमान कर रही है भाजपा : श्यामलाल पाल

अमेठी। समाजवादी पार्टी (सपा) की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत डबल इंजन की सरकार को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि यह बाबा साहब डॉ भीमराव आंबेडकर के विचारों और उनकी सोच का अपमान कर रही है। अमेठी के घटकौर में समाजवादी पार्टी के पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान भाजपा को संविधान विरोधी करार दिया।

उन्होंने कहा कि भाजपा देश में सामंतशाही व्यवस्था लागू करना चाहती है और उसे संविधान में भरोसा नहीं है। पाल ने कहा कि जिस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने बनाया है, वो संविधान खतरे में है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र और राज्य की सरकार बाबा साहब के विचारों और उनकी सोच का अपमान कर रही है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संविधान बचाने की मुहिम छेड़ दी है और आज इसी के तहत समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर पहुंचकर इस सामंतवादी सरकार को उखाड़ फेंकने का आवाहन कर रहे हैं। पाल ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है, जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, त्योहार मनाते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का काम कर रही है।

फ्री मूवमेंट अभियान के पहले ही दिन हिंसा: व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश

मणिपुर। महीनों तक चली जातीय अशांति के बाद स्वतंत्र आवाजाही के पहले दिन ताजा हिंसा देखने को मिली, जिसमें कांगपोकपी इलाके में एक सार्वजनिक बस पर हमला किया गया। यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों को 8 मार्च, 2025 से पूरे राज्य में अप्रतिबंधित आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, साथ ही व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था।

सेनापति जिले जाने वाली बस पर हमला उस समय हुआ जब कांगपोकपी जिले के गमगीफाई इलाके में भीड़ ने यात्री वाहन पर पत्थर फेंके। बस पर कथित तौर पर कुकी जनजातियों द्वारा हमला किया गया था, जो तब तक कोई स्वतंत्र आवागमन नहीं चाहते हैं जब तक कि राज्य से अलग प्रशासन की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया, जिससे कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इससे पहले मुख्य सचिव ने बयान में कहा था कि राज्य

परिवहन की बसें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के संरक्षण में चलेंगी ताकि जनता की असुविधा को कम किया जा सके और राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की दिशा में पहल की जा सके।

मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में शनिवार को मेइती संगठन द्वारा आयोजित शांति मार्च को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि यह प्रदर्शन अंतर-जिला बस सेवाओं को फिर से शुरू करने की सरकार की पहल के दिन हो रहा था। इस पहल का उद्देश्य लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना था। सुरक्षा बलों ने इंफाल से लगभग 18 किलोमीटर दूर सेकमई में फेडरेशन ऑफ सिविल सोसायटी ऑर्गनाइजेशन द्वारा निकाले गए जुलूस को रोक दिया और आयोजकों से सरकार की मुक्त आवाजाही पहल में शामिल होने को कहा।

राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गत 20 फरवरी को राज्य के लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को सात दिनों के भीतर स्वेच्छा से सौंपने का आग्रह किया था

मणिपुर के तीन जिलों में हथियार सुरक्षा बलों को सौंपे गए

इंफाल। हिंसाग्रस्त मणिपुर के तीन घाटी जिलों में लोगों ने 16 प्रकार के आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद सुरक्षा बलों को सौंपे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गत 20 फरवरी को राज्य के लोगों से लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियारों को सात दिनों के भीतर स्वेच्छा से सौंपने का आग्रह किया था और आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बाद में, उन्होंने पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों के लोगों की मांग पर समय सीमा छह मार्च शाम चार बजे तक के लिए बढ़ा दी थी। अधिकारियों ने बताया कि बिष्णुपुर जिले में राज्य पुलिस की कमांडो इकाई को सौंपे गए आग्नेयास्त्रों में दो एसएलआर राइफल, खाली मैगजीन, एक इंसास राइफल, .303 राइफल, एक हथगोला और गोलियां शामिल थे।

जिले के कुम्बी और फोगाकचाओ इखाई पुलिस थानों में लोगों ने स्थानीय रूप से निर्मित दो बोल्ट

एक्शन राइफल, देसी पिस्तौल और एक एसएमजी कार्बाइन सुरक्षा बलों को सौंपे।

इम्फाल पूर्व में तीन पिस्तौल, गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा और तीन ग्रेनेड राज्य पुलिस की कमांडो इकाई तथा पोरोम्पट, एंड्रो और इरिलबुंग पुलिस थानों में सौंपे गए। अधिकारियों ने बताया कि हथियार, गोलाबारूद और रेडियो सेट इम्फाल पश्चिम जिले के मयांग इम्फाल पुलिस थाने में जमा करा दिए गए।

महिलाएं जिन्होंने स्वयं के दम पर स्वावलंबन की डगर चलकर समाज में पेश की मिसाल

बागपत। समाज में उन महिलाओं की कमी नहीं, जिन्होंने स्वयं के दम पर स्वावलंबन की डगर चलकर न केवल अपने परिवार को संभाला। बल्कि रोजगार देकर दूसरों के घरों के चूल्हे जलवाने की भी मिसाल पेश की।

पति की नौकरी छूटने पर थामी कमान और छू लिया आसमान

यह कहानी है बसौली गांव निवासी हाईस्कूल उत्तीर्ण विमला भारद्धाज की जो कभी पाई-पाई को तरसती थीं, लेकिन आज आठ घरों के चूल्हे जलवा रहीं। बात कुछ यूं है कि पति अश्वनी की रेलवे में आउट सोर्सिंग की नौकरी छूटने पर 2020 में वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ गईं। प्रतिदिन 10 रुपये बचत कर जमा करने लगीं। कुछ दिन बाद ब्यूटीशियन का प्रक्षिण लेकर गांव में ब्यूटी पार्लर खोल स्वरोजगार की डगर थामी।

कुछ कमाई होने लगी तो 20 हजार रुपये लगाकर एलईडी बल्ब तैयार करने का काम शुरू किया। काम बढ़ा तो फिर दूसरी आठ महिलाओं से भी एलईडी बल्ब बनवाने लगीं। खुद 30-35 हजार रुपये कमाने के साथ दूसरी महिलाओं की प्रत्येक की आठ-दस हजार रुपये कमाई होने लगीं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नामचीन हस्तियां उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं।

बहू क्या मर्दों के साथ काम करेगीं

नौरोजपुर गुर्जर निवासी रजनी ने चार साल पहले स्वयं सहायता समूह गठित किया, लेकिन स्वरोजगार की राह नहीं सुझी। कोरोना काल में सरकार ने बिजली बिलों की वसूली का का जिम्मा समूह की दीदियों को दिया तो उनका विद्युत सखी पद पर चयन हो गया। वसूली को घरों में जाना शुरू किया तो सासू ने तंज कसा कि बहू क्या अब मर्दों के साथ काम करेगी, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुई। बिल वसूली को घरों में जाती तो लोग तंज कसते कि ये तो ठगनी है। भला घर में काम करने वालीं को बिल वसूली का काम कैसे मिल गया।

मगर, हिम्मत नहीं हारी और ऊर्जा निगम के जेई तथा एक्सईएन को गांव में बुलाकर लोगों को यकीन दिलाया कि ये बिल वसूली के लिए अधिकृत है। फिर क्या था वे वसूली मिशन पर निकल पड़ी और देखते ही देखते सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गईं।

वर्ष 2023 में 42 लाख रुपये वसूली करने पर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 2024 में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। चालू वित्त वर्ष में छह माह में ही ढ़ाई करोड़ की वसूली कर कर चुकी हैं। प्रत्येक माह 40-50 हजार रुपये कमाने से परिवार को न केवल गरीबी रेखा से बाहर निकाला, बल्कि जीवन स्तर भी ऊंचा उठने लगा। वे अब गांव ही नहीं, बल्कि जिले में बिजली वाली दीदी के रूप में मशहूर हो चुकीं हैं।

हुनर के दम पर मुंबई में मचाई धूम

बड़ागांव की आसमां पांच साल पहले एक आम बुनकर थीं, लेकिन वर्ष 2018 में एक जिला, एक उत्पाद योजना के तहत बागपत में गृह सज्जा के उत्पाद शामिल होने पर उनकी किस्मत ही बदल गई। प्रशिक्षण से अपने हुनर को ऐसा निखरा कि अब उनके हाथ के बने पर्दे, चादर, तकियों के कवर, पायदान, झोले आदि की काफी डिमांड है। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय आजीविका मिशन से मुंबई में लगे राष्ट्रीय स्तर के मेले में प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से स्टॉल आवंटित करवाकर उन्हें वहां भाग लेने को भेजा। मुंबई में उनकी कमाई लाखों में हुई। वहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस समेत मुंबई की नामचीन हस्तियों ने उनके स्टाल पर जाकर उनका हौंसला बढ़ाया। आसमां बोलीं कि पहले उनकी साल में एक-डेढ़ लाख रुपये की कमाई होती थी, लेकिन अब वह छह-सात लाख रुपये कमा रहीं हैं। जिससे अब वह बच्चों को पढ़ाने के साथ हंसी खुशी से परिवार चला रहीं हैं। उपायुक्त स्वतः रोजगार अखिलेश चौबे कहते हैं कि आसमां के बनाए हैंडलूम उत्पादों की मुंबई में खासी बिक्री हुई हैं।

पापों की गठरी लेकर गया था औरंगजेब

औरंगजेब के समय बुंदेलो, सतनामियों, सिक्खों का भी सफल प्रतिरोध हुआ था। इसके अलावा औरंगजेब दक्षिण में मराठों से युद्ध करते थक गया। निराश होकर बीमार पड़ गया था तब उसने अपने दो बेटों आजम और कामरान को पत्र लिख कर प्रायश्चित करते हुए कहा- मैंने किसी का भला नहीं किया है। मैं पापों की गठरी लेकर जा रहा है। आजी वसीयत में भी औरंगजेब ने अपने पापों और अत्याचारों के लिए प्रायश्चित किया था। एक इतिहासकार ने लिखा भी है- जिस तरह स्पेन के फोड़ ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया। उनके लिए औरंगजेब का जीवन एक सीख होना चाहिए जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं और भारत में औरंगजेब जैसे इस्लामिक राज्य की स्थापना का मंसूबा पाले बैठे हैं। उनको यह जानना चाहिए कि 50 सालों तक निर्बाध भारत कट्टरपंथी अत्याचारी औरंगजेब के शासन ने ही हिन्दुओं को एकजुट और सशस्त्र प्रतिरोध के लिए खड़ा कर मुगल शासन के अंत की नींव रखी थी। यह भी बात याद रखनी चाहिए कि देश के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भारत भूमि के विभाजन के मुख्य किरदार जिन्ना की कब्र पर पाकिस्तान में जाकर फूल चढ़ाए थे उनका बाद में भारतीय राजनीति में किस तरह पराभव हुआ है किसी से छिपा नहीं। किसी भी देश का बहुसंख्यक समाज का खलनायक उसी देश के अल्पसंख्यक समाज का नायक कैसे बन सकता है ? भारतीय संस्कृति धर्म की रक्षा करने वाले दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय सिख समाज के नौवें गुरु तेगबहादुर का कत्ल भी औरंगजेब ने ही किया था। इसके अतिरिक्त अंतिम गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझारू सिंह औरंगजेब की सेना से लड़ते हुए बलिदान हो गए थे। लेकिन इन सब जघन्य घटनाओं के चलते गुगल साम्राज्य जर्जर हो गया था। महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। इसका कारण है औरंगजेब को सदा महाराष्ट्र चीफ अबू आजमी द्वारा न्यायप्रिय और दयालु शासक बताया जाना। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल सा आ गया। लगभग महाराष्ट्र के सभी दलों के नेताओं ने आजमी के बयान की तीव्र निन्दा की। इसके चलते आजमी को विधान सभा से कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके पहले भी मई 2011 में नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र पर चादर और फूल चढ़ाया था। कब पर जाने के दौरान तत्कालीन सांसद उनकी ही पार्टी के इलियास भी उपस्थित थे। दरअसल ओवैसी का औरंगजेब की कब्र पर जाना और आजमी हारा औरंगजेब को अच्छा शासक बताना एक संयोग नहीं बल्कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम है। ये आइडियोलॉजी का छेड़ा हुआ युद्ध है। हिंदुओं के दमनकर्ता, क्रूर संहारक और जेहादी के रूप में प्रस्थापित मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने की कवायद है। देश के तमाम मुस्लिम और कम्युनिस्ट इतिहासकार औरंगजेब को महान शासक मानते हैं। कुछ मुस्लिम-चरमपंथी इस बात से खुश होते हैं कि औरंगजेब ने तलवार के दम पर हिन्दुओं पर पूर्ण इस्लामिक शासक की तरह से शासन किया। ज्यादातर आज भी लोग औरंगजेब की कब्र पर इसलिए नहीं जाते, क्योंकि वह अत्याचारों शासक था। ओवैसी की पार्टी ने औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने का यह समय इसलिए चुना था क्योंकि उस समय मथुरा और वाराणसी में मंदिर-मस्जिद विवाद चल रहा है। यह सर्वविदित और ऐतिहासिक तथ्य है कि इन दोनो जगहों पर हिन्दुओं के आराध्यों के विशाल मंदिरों को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बना दी थी। औरंगजेब के धार्मिक उन्मादी स्वभाव का पता केवल औरंगजेब के 1662 और 1669 के दो फरमानों से लगाया जा सकता है जिसमें उसने समस्त हिन्दू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इसी के तहत काशी मथुरा सोमनाथ सहित हजारों प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और ध्वस्त कर दिया गया था। शायद ओवैसी की पार्टी और अबू आजमी का यह भी सोचना हो कि वह मुसलमानों के अंदर औरंगजेब के बहाने अभियान भरकर उनमें विजयी इस्लामिक चेतना पैदा कर सकते हैं परन्तु आजमी और ओवैसी तथा उनकी पार्टी यह भूल गई कि-औरंगजेब मराठों के प्रतिरोध को दबाने के लिए 27 साल तक दक्षिण में फंसा रहा। प्रतिरोध को कुचलना तो दूर उसे दबा भी नहीं सका। औरंगजेब की सेना एक जगह मराठों के क्षेत्र पर कब्जा कर पाती तब तता दूसरे क्षेत्र और किले मुगलों से मराठे आजाद करा लेते। यह नहीं भूलना चाहिए कि औरंगजेब के शासन काल में शिवाजी महाराज में पूरे महा राष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और गुजरात के बड़े भाग पर स्वतंत्र मजबूत शासन स्थापित कर लिया था। इतना ही नहीं मराठों से लड़ते-लड़ते औरंगजेब का मजबूत शासन कमजोर हो गया था। मुगल शासन की नींव हिल गई थी। इसी के चलते जाटों ने आगरा, मथुरा और दिल्ली के बीच जबरदस्त लड़ाई लड़ी। जाट सरदार राजाराम ने मुगलों की आन-बान-शान के प्रतीक आगरा के निकट बेहद सुरक्षित सिकंदरा अकबर के मकबरे पर तीन हमले कर बट लिया था। दो हमको में वह सफल नहीं हुआ, जबकि अंतिम हमले में वह मकबरे को छूटने में सफल होगया। यह कारनामा राजाराम ने मार्च-1688 में किया था। उसने न केवल मकबरे को हटा। बल्कि अकबर की अस्थियों के कब से निकाल कर जला दिया। राजाराम का दिल्ली-आगरा राजपथ पर लगभग पूरी तरह कब्जा था। इतिहासकार पो. कानूनगो के अनुसार - औरंगजेब के बड़े-बड़े अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए टैक्स राजाराम को इस बात के लिए देते थे कि वह उनके इलाके में हमला करें। मारवाड़ के सेनापति दुगार्दास राठौर ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को खुला संरक्षण दे दिया था और लंबे संघर्ष के बाद अजीत सिंह को मारवाड़ के सिंहासन पर आरुढ़ करवाया था।

भारतीय सड़कें हादसों के मामले में तीसरे स्थान पर

`भारत की सड़कें हादसों के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। प्रतिवर्ष सड़कों पर वाहनों में इजाफा, अतिक्रमण से सिकुड़ती सड़कें शून्य फिटनेस और जुगाड़ के चलते वाहन देश में चुनौती बन चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक घोषणापत्र 2015 में 2030 तक सभी देशों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर इसमें होने वाली मौतों में पचास प्रतिशत तक कमी लाने का संकल्प है। भारत ने भी इस घोषणापत्र में दस्तखत किया है। इस के अनुरूप विश्व के 108 देश अबतक सड़क दुर्घटनाओं में 10 प्रतिशत कभी लाने का प्रयास कर रहे हैं जबकि इनमें शामिल दस देश इस अवधि पचास प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। इसके विपरीत भारत में सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। भारत में जिस तेजी से सड़कों का विकास हो रहा है उसी के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। शून्य दुर्घटना डिजाइन के आधार पर ही मार्गों के निर्माण की मंजूरी का विधान देश में होना चाहिए। सड़कों के निर्माण में घुमावदार मोड़ों को न्यूनतम करते हुए लंबी दूरी तक दृश्यता स्पष्ट होनी चाहिए। परन्तु इसके विपरीत देश के राजमार्ग सहित राष्ट्रीय मार्गों पर स्थान-स्थान पर घुमाव, उतार दिखाई देते हैं। यही कारण है कि अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए चर्चित नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के लिए इंजीनियर और सरकारी क्षेत्र को जिम्मेदार ठहराया है।

एक बार फिर सरकारी सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया है। तमाम प्रयासों के बावजूद देश में बढ़ रहे सड़क हादसों के लिए बतौर मंत्री स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने दो टूक कहे कि इतने हादसों और मौतों के लिए सबसे अधिक

जिम्मेदार सिविल इंजीनियर और सरकारी सिस्टम है। डीपीआर बहुत खराब बनती है। एक्सेस कंट्रोल रोड के कंपाउंड वाल का कोई डिजाइन हमारे पास नहीं है। विभागीय अधिकारियों के पति अविश्वास जताने हुए उन्होंने इंटरनल रोड फेडरेशन से कहा है कि- रोड सेफ्टी माइनेज और रोड पार्किंग का अंतरराष्ट्रीय स्तर का मॉडल तैयार कर दें। सरकार अनिवार्य रूप से लागू करेगी।

विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों ने किया भगवान बुद्ध की आदमकद प्रतिमा का अवलोकन

वाराणसी। विद्युत नियामक आयोग के 50 सदस्यों ने वाराणसी में सारनाथ पहुंचकर भगवान बुद्ध की आदमकद प्रतिमा का अवलोकन किया। संग्रहालय में राष्ट्रीय चिह्न शीर्ष सिंह की चमक देखकर सभी अभिभूत हुए। तीन देशों व भारत के अन्य राज्यों से आए विद्युत नियामक आयोग के 50 सदस्य शनिवार को सारनाथ में राष्ट्रीय चिह्न की चमक देख कर अभिभूत हुए। शाम को लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा से रूबरू हुए।

विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश के चेयरमैन अरविंद कुमार के नेतृत्व में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश व प्रदेश के अन्य राज्यों से आए नियामक आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए आए 50 सदस्यीय दल अपराह्न 3:30 बजे सबसे पहले थाई बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की आदमकद प्रतिमा का अवलोकन करने के बाद पुरातात्विक संग्रहालय पहुंचे। संग्रहालय में राष्ट्रीय चिह्न शीर्ष सिंह की चमक देखकर अभिभूत हुए। उपखंड अधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने स्मारकों के इतिहास व बुद्ध के जीवन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान चेयरमैन देवेंद्र शर्मा,पी राव कुमार, अवर अभियंता राज कुमार, पर्यटक पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार अपनी टीम के साथ लगे थे।

होली आते ही शुरू हुई फाग की बयार, गांवों में उड़ने लगा गुलाल

राजपुर (कानपुर देहात)। बुंदेलखंड की सीमा से सटे यमुना पट्टी में होली की तैयारी जोरो पर है। गांवों में फाग की महफिलें सजने लगी हैं। टोलियां ढोलक की थाप, हरमोनियम व झीके की धुनों के बीच फाग गा रहे हैं। होली के लिए जमकर खरीदारी चल रही है। महिलाएं घरों में मेवा और चिप्स तैयार कर रही है। वहीं, बाजार में रंग-गुलाल और पिचकारी की दुकानें सज गई हैं।

होली पर फागुनी रंग निराला होता है। बीहड़ पट्टी में होली पर फाग की अलग छाप है। इसकी झलक यमुना बेल्ट के गांव बेहमई, खोजा रामपुर, जैसलपुर, गौरीरतन बांगर, भारत, दमनपुर, सिलहरा, सलेमपुर में देखी जा सकती है। त्योहार करीब आते ही फाग की जमातों ने फागुनी रंग जमाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को राजपुर के भाल गांव में धीरेंद्र द्विवेदी के घर के बाहर में फगुआरों की महफिल सजी और जमकर फाग गायन किया गया।

ढोलक वादक नरेंद्र सिंह उर्फ चंचल के साथ फाग गायक रामप्रसाद, बब्बू दीक्षित, बनाफर मास्टर, अजय पाल सिंह, रविन्द्र सिंह, ओंकार सिंह, बुलबुल, सरमन, छेदीलाल, रधु, इंद पाल, पूर्व शिक्षक रमेश सिंह ने गायन से समां बांध दिया। भाल गांव के प्रधान अरविंद दीक्षित बब्बन ने लोगों को अबीर-गुलाल लगाकर फाग कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में भी गांव में फाग गायकी की धूम रहती है। इससे पुरानी परंपरा जिंदा है।

होली की तैयारी, खूब हो रही खरीददारी

होली को लेकर सिकंदरा, राजपुर, शाहजहांपुर, रसधान की बाजारों में खरीदारी के लिए खूब भीड़ उमड़ रही है। पर्व पर खुशियों का रंग अपनों के संग बिखेरने को जरूरत के हिसाब से खरीदारी की गई। रंग-गुलाल और पिचकारी की दुकानों पर खूब ग्राहक उमड़े। शुक्रवार को सिकंदरा में साप्ताहिक बाजार में खूब भीड़ रही। पकवान बनाने के सामान की लोग खरीदारी करते दिखे। रंग, गुलाल और पिचकारियों की दुकानों पर बच्चों और युवाओं का जमावड़ा दिखा। चेहरे को ढकने के लिए मुखौटे तो बालों को ढकने के लिए तरह-तरह की टोपियों की खूब बिक्री हो रही है।

चाकू की तरह है मोबाइल, सर्जन के हाथ में हो तो अच्छा, बदमाश के हाथ में हो तो नुकसान :राजेन्द्र सिंह

बिजनौर। बिजनौर की काकरान वाटिका में रविवार को जाट संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने कहा कि नशे को लेकर समाज में स्थित भयावह होती ही जा रही है। सूखा नशा या इंजेक्शन लेने का चलन बढ़ा है। हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, लिहाजा गांठ बांध ले कि नशे से दूर रहना है। राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस काम में महिलाओं को भी मदद करनी होगी। 8% ठेके महिलाओं के विरोध के चलते हटे हैं। शराब पीने वाले की जेब से निकलने वाला पैसा उनके परिवार और समाज के काम आएगा।

नहीं बदले तो पिछड़ जाएंगे

राजेंद्र सिंह ने कहा कि दुनिया और समाज तेजी से बदल रहा है। अगर उसके मुताबिक हम नहीं बदले तो पिछड़ जाएंगे। नदी की तरह बहना है। तालाब ठहर जाता है तो मर जाता है अब तालाब में लोग पशुओं को भी पानी नहीं पिलाते। इसलिए दुनिया के साथ खुद को भी अपडेट करते रहें। जितना संभव हो सके, दूसरे की मदद करें। अगर मदद करने में सक्षम न हों, तो कि सी का अहित न करें। ईमानदारी हमारा मूलभूत गुण था, उस पर चलें।

उन्होंने युवाओं से कहा कि हम अपने जीवन के हर रोज 24 घंटे में से तीन-चार घंटे का समय मोबाइल पर व्यतीत कर रहे हैं। मोबाइल उस चाकू की तरह है जो किसी सर्जन के हाथ में होता है, तो ऑपरेशन करके मरीज को स्वस्थ करता है। अपराधी के हाथ में होता है तो वह चाकू से अपराध को अंजाम देता है। अपने बच्चों को भी मोबाइल से दूर रखें। सोशल मीडिया पर चल रहा कंटेंट उनके दिमाग में कूड़ा भर रहा है। हालांकि यूट्यूब या अन्य किसी प्लेटफार्म से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो वह फायदेमंद है।

महिलाओं ने जब ठानी जिदः इनके हौसले के आगे पर्वत झुके, चट्टानें पड़ीं कमजोर

अलीगढ़। महिलाओं ने जब जिद ठान कर खुद को मुकाम देने की ठानी तो कठिन परिस्थितियों ने भी उनका रास्ता छोड़ कर राह हमवार कर दी। उनके हौसले के आगे पर्वत झुक गए और दृढ़ता के आगे चट्टानें कमजोर पड़ गईं।

महिला दिवस पर अलीगढ़ में मौजूद ऐसी ही महिलाओं का जिक्र करना प्रासंगिक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी संगीत सिंह की पूरी शिक्षा प्रयागराज से हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पिता की प्रेरणा से वह 1994 में आईएएस बनीं। उनकी सफलता के पीछे परिवार के साथ-साथ उनके ससुर का बेहद योगदान रहा। सिविल सेवा की प्री परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद ससुर ने एक स्टडी टेबल लाकर दिया।

प्रोत्साहित किया कि वह आगे बढ़ें। वर्तमान में वह अलीगढ़ मंडल की आयुक्त हैं।

अपूर्वा दुबे आईएएस :

यूपीएससी की टॉपर रहीं

2013 बैच की अफसर अपूर्वा यूपीएससी की टॉपर रह चुकी हैं। उनके पिता डॉ. संजय दुबे प्रसार भारती नई दिल्ली में अतिरिक्त महानिदेशक थे। दादा डॉ. केएन दुबे लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में प्रोफेसर रहे। अपूर्वा दुबे की स्कूली पढ़ाई अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित स्कूल विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय से हुई। उन्होंने आईएएस अधिकारी विशाख जी अय्यर से शादी की है। अपूर्वा वर्तमान में अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर हैं।

अरीबा नोमान, प्रशिक्षु आईपीएस : मामू का सपना पूरा किया

2022 बैच की आईपीएस अरीबा नोमान ने सन 2021 में यूपीएससी 2021 ऑल इंडिया 109 वीं रैंक के साथ पास की। अरीबा ने आईपीएस बनकर अपने मामू का सपना पूरा किया था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की रहने वालीं अरीबा के पिता नोमान अहमद नेशनल इंश्योरेंश कंपनी में सुल्तानपुर में ही मैनेजर रहे। अरीबा ने 10वीं तक की पढ़ाई शहर के ही स्टेला मॉरिस कान्वेंट स्कूल से की। वह वर्तमान में अलीगढ़ में ट्रेनी आईपीएस पद पर हैं।

महिमा राजपूत, एसडीएम खैर : पहले प्रयास में सफलता की हासिल

मंडल के अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे के मोहल्ला राजपूत कॉलोनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता की बेटी महिमा ने पहले ही प्रयास में पीसीएस- 2020 की परीक्षा में आठवीं रैंक हासिल की। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश चंद्र चौहान के घर 18 दिसंबर 1995 को जन्मी महिमा आईएएस बनना चाहती हैं। गजरौला के सेंटमैरी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ीं। महिमा ने वर्ष 2012 में सौ फीसदी अंक हासिल कर हाईस्कूल में कीर्तिमान बनाया था।

2019 में आईआईटी इंदौर से एमएससी की पढ़ाई पूरी कर वह दिल्ली पटेल नगर में लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयार की।

घूँघट की बगावत

9 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट : भारत में भ्रष्टाचार बेलगाम

भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के वायदे वफा होते नजर नहीं आते। दुनिया भर में भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करने वाली गैर-सरकारी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट बताती है कि-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए नारे - न खाऊंगा न खाने ने दूंगा के बावजूद भारत में भ्रष्टाचार बेलगाम है।

कारोबारियों के साथ साथ राजनेताओं और नौकरशाहों के यहां से भी छापेमारी के दौरान नगदी की बरामदगी का अर्थ यही है कि खाने खिलाने का सिलसिला बंद तो नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा धारणा सूचकांक सीपीआई पर आधारित -2024 के लिए हाल मे जारी भ्रष्ट देशों की सूची बताती है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत सपना ही बना हुआ है। इस सूची में शामिल 180 देशों में भ्रष्टाचार के आसनों भारत 38 अंकों के साथ 96 वें स्थान पर है जबकि साल 2023 में भारत 39 अंकों के साथ 93 वें स्थान पर था। दरअसल सीपीआई में जिस देश को अधिकतम अंक मिलते हैं. वहां भ्रष्टाचार कम माना जाता है।

घटते अंक ज्यादा भ्रष्टाचार का प्रभाव होते हैं, जिनके साथ-साथ सूचकांक में देश की रैंकिंग भी बढ़ती जाती है। हमारे देश में भ्रष्टाचार राजनीतिक मुद्दा बन कर रह जाता है। इसलिए यह जानना भी जरूरी है कि- वर्तमान मोदी सरकार और पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार के शासन काल में भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हर साल जारी की जाने वाली भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक आधारित 180 देशों की सूची बताती है कि पिछले दस सालों में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है।

पिछले दस सालों में भारत ने इस सूची में सबसे बेहतर प्रदर्शन साल 2015 में किया था। जब उसे रैंकिंग में 76 वां स्थान हासिल हुआ था। वैसे साल- 2008 और 2007 में भारत क्रमशः 70वें और 72 में स्थान पर रहा। यानी दोनों हो सरकारों के आरंभ काल में भ्रष्टाचार कम होता नजर आया परंतु फिर बेलगाम हो गया। हमारा पड़ोसी और प्रतिद्वंदी देश चीन 43 अंकों के साथ 76 वें स्थान पर बना हुआ है। लगभग 20 करोड़ लोगों को प्रतिमाह पांच किलो राशन मुफ्त देने की जरूरत भारत देश की खुशहाली का प्रमाण तो हरगिज नहीं हो सकता। बढ़ती बेरोजगारी तथा शिक्षा स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था भी वास्तविक विकास के दावों पर सवालिया निशान है। इसलिए हमें आंकड़ों पर आधारित आर्थिक प्रगति पर आत्ममुग्धता से उभर कर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर आधारित इस सूची में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों से जरूरी सबक भी सीखने होंगे। 90 अंकों के साथ डेनमार्क इस सूची में सबसे ऊपर है जिसका अर्थ है कि वहां नाममात्र का ही भ्रष्टाचार है ।88 अंकों के साथ फिनलैंड इस सूची में दूसरे स्थान पर है जिसे विश्व का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। 84 अंकों के साथ सिंगापुर तीसरे स्थान पर 83 अंकों के साथ न्यूज़ीलैंड चौथे और 81 अंक के साथ लक्जमबर्ग पांचवें स्थान पर है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब विदेश में बसने के इच्छुक भारतीय छोटे-छोटे देशों को अपना गंतव्य बनाने लगे हैं। क्या यह इस बात का संकेत नहीं है कि ये देश उन्हें हर दृष्टि से बेहतर जीवन स्तर का विकल्प नजर आते हैं।

बेशक, सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। आठ अंकों के दक्षिण सूडान 180 देश देशों में सबसे भ्रष्ट देश है, जबकि सोमालिया और बेनेजुएला नौ और दस अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे भ्रष्ट देश हैं। उनके बाद सीरिया, लीबिया, इरिट्रिया, यमन इक्वेटोरिल गिनी का नंबर आता है। वैसे इस सूची में रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन (ब्रिटेन) और जर्मनी जैसे प्रभावशाली देश क्रमशः 154वें, 28वें, 25वें, 20वें और 15वें स्थान पर हैं।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुखिया फ्रेंकोइस वेलेरियन कहते हैं कि- भ्रष्टाचार एक उभरता हुआ खतरा है। जो विकास को रोकता है। साथ ही लोक क्षेत्र में गिरावट, अस्थिरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन को बढ़ाता है। कहना नहीं होगा कि - ज्यादा भ्रष्टाचार वाले देश इन तमाम खतरों से रू-ब-रू हैं। यह भी कि इन खतरों से निकले बिना देश और समाज के सर्वांगीण विकास के दावे संदेह और सवालों में से घिरे होंगे। रहेंगे। हमारे नीति-नियंता इस बात पर संतोष जता सकते हैं कि पड़ोसी देशों में पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे खराब है। साल-2023 में पाकिस्तान 29 अंकों के साथ 135वें स्थान पर था लेकिन बीते साल वह 25 अंकों के साथ 135वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूची में श्रीलंका और बांग्लादेश की रैंकिंग-बताकर हमारे देश के सत्ताधीश अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। कई साल इस सूची में श्रीलंका 101वें और बांग्लादेश 149वें स्थान पर हैं लेकिन हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश भूटान है। भ्रष्ट देशों की रैंकिंग में 18वें नंबर पर भूटान को दुनिया के खुशहाल देशों में भी गिना जाता है। जाहिर है वायदों और बातों के विपरीत वास्तविकता व्यवस्था और मानसिकता पर सवाल खड़े करते हैं जिसके जवाब खोजे बिना विश्व की तीव्र वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं गले लगाएं बेहतर देश नहीं बन पाएंगे। आर्थिक प्रगति के आंकड़ों के महत्व से इनकार नहीं है, लेकिन राष्ट्र की असली प्रगति समाज के सर्वांगीण विकास और खुशहाली में होती है।

आधी आबादी की शिक्षा व खेल में भागीदारी

राजनीतिक रूप से काफी अहम प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैंसर, जमुई समेत विभिन्न जिलों में एक दर्जन से अधिक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बेतिया और सुपौल में स्टेडियम के आधुनिकीकरण, कटिहार में राजेंद्र स्टेडियम को स्पोर्टस काम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने की घोषणा की है।

बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में 2024-25 बजट पेश किया है बजट चर्चा में खेलों में महिलाओं की भागीदारी बनाने की नीतीश कुमार के विजन को छाप स्पष्ट है। बिहार में खेलों के लिहाज से अगले कुछ महीने महत्वपूर्ण साबित होते हैं। जून में बिहार में महिला विश्वकप कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें भारत समेत 15 देशों की महिला खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगी। इसके अलावा सेपक टकराव भी पहली बार बिहार में आयोजित होने वाला है। नीतीश सरकार जिस प्रकार खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर कार्य कर रही है। उम्मीद है कि भविष्य में बिहार से कई धाकड़ महिला खिलाड़ी निकलेंगी, जिन पर पूरे देश को गर्व होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2004-05 में बिहार की ग्रामीण महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया कि राज्य में ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा के लिए प्रदेश लेने का अनुपात मात्र 1.21 प्रतिशत (पूरे देश में सबसे निचला स्थान) था। शहरों में भी कमोवेश स्थिति अच्छी नहीं थी।

ये रिपोर्ट तत्कालीन शासनकाल का स्याह पक्ष उजागर करती है। जब लड़कियों केलिए घर की दहलीज लांघना असंभव था। पढ़ाई के सपने जंगलराज के आतंक के आगे चकनाचूर हो जाते थे। खेलों में भाग लेने की चाहत मन के मन के किसी कोने में दम तोड़ देती थी लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।2005 में बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद नीतीश कुमार ने आधी आबादी के आर्थिक और सामाजिक मजबूती सुनिश्चित की। नीतीश सरकार ने एक के बाद एक ऐसे निर्णय लिए जिससे न केवल शिक्षा में भागीदारी बढ़ी बल्कि खेलों में भी दमखम दिखाया । आमिर खान की फिल्म - दंगल का वह संवाद-म्हारी छोरियां छोरों से कम

है कैऱ आज बिहार पूरे गर्व के साथ कह सकता है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्रों लड़कों से कम नहीं।

थाइलैंड में आयोजित पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर नालंदा समेत पूरे बिहार को गर्व से भर देने वालो गोल्डी कुमारी हो या सीनियर नेशनल स्वीमिंग चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली भारत की सर्वश्रेष्ठ तैराक पटना की माही श्वेता राज या कि भारत की जुनियर महिला फुटबाल टीम में चयनित सिवान की खुशी कुमारी... ऐसी महिला खिलाड़ियों की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता ओं में अपना लोहा मनवाया । बहुत अधिक दिन नहीं गुजरे है। चार महीने पहले नवम्बर महीने की राजगीर की खुशनुमा यादों को ही टटोलिजिए जब बिहार वीमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कर रहा था। स्टेडियम में उमड़ी भीड बता रही थी कि- अब बिहार की हवा बदल चुकी है। इस प्रतियोगिता में भारत समेत चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया जैसी टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के ठीक पहले आयोजित गौरव यात्रा को भी सराहा गया था जिसको उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी एवं जागरुकता बढ़ाना था।

सरकारी स्तर पर इस तरह की गंभीरता की सराहना जितनी की जाए कम है। नीतीश सरकार के ऐसे गंभीर प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी बिहार देते हैं।

पिछले साल उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार की बेटियों ने' लॉन बॉल की ट्रिपल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पी.टी. उषा ने बिहार की बेटियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मजबूत खेल राज्य के रूप में उभर रहा है। दर असल सरकार के प्रयासों में बिहार में एकतरफ खेलों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण हुआ वहीं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को खेलों में भाग लेने केलिए प्रोत्साहित किया गया। यहां पर प्रेरणा योजना का और मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना का भी उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

प्रेरणा योजना के तहत सरकार खोज प्रतियोगिताओं द्वारा चयनित खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर बेहतर खिलाडी बनाने में जुटी है। खोज प्रतियोगिता दर असल बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से नीतीश सरकार राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। सरकार खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि - 2032 और 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों में पदक जीत सकें।

भूजल अनेक जहरीले रासायनिकों की वजह से पीने लायक नहीं

भारत की तीस करोड़ की आबादी को फताल के शुद्ध पानी से वंचित होना पड़ रहा है। चंडीगढ़ स्थित प्रयोगशाला के परीक्षण के अनुसार - दिल्ली में जमीन के नीचे के पानी में क्लोराइड की मात्रा तय सीमा में बहुत अधिक एक हजार फीसदी पाई गई। इसी प्रकार कैल्सियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, फेरिक (लोहा) और कैडमियम की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इन तत्वों से मुक्त पानी पीने से हृदय घात, किडनी पर बुरा असर, लीवर का संक्रमण, गैस्ट्रिक कैंसर, दांत संबंधित बीमारियां, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर, त्वचा संबंधी रोग, तनाव, अस्थमा, थायराइड, हृदय संबंधी रोग, डायरिया, और अन्य संबंधी अनेक समस्याएं बहुतायत से देखी जा रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भू-जल के प्रदूषित होने के मद्देनजर बड़ी इकाइयों को बंद करने या आबादी से दूर स्थानांतरित करने का निदेश दिया था। आदेश दिया था जिसका पालन राज्य सरकारों ने किया, लेकिन आज भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हरिद्वार, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दूसरे तमाम शहरों में औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं जिसपर तत्काल गौर करने की आवश्यकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन में आर्सेनिक अधिकतम सुरक्षित स्तर दस पार्ट्स पर बिलियन (पीपीबी) माना है। गौरतलब है कि दुनिया में 15 करोड़ लोग नियमित रूप से इससे अधिक आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, अमेरिका सहित दुनिया के ऐसे तमाम देश हैं जहां आर्सेनिक, नाइट्रेट कुछ खास तरह के लवण भूजल में घुले मिलते हैं। गौरतलब है कि विकसित देशों में नयी तकनीक के जरिये भूजल के विषाक्त होने की समस्या को काफी कुछ हल कर चुके हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में अभी इस दिशा में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है जिससे लोगों को जहरीले पानी पीने की जरूरत से बचाया जा सके। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और असम की तरह छत्तीसगढ़ ऐसा तीसरा राज्य है जहां पानी में आर्सेनिक, नाइट्रेट जैसे जहरीले रासायनिक तत्व बहुतायत मात्रा में पाये जाते हैं। कोलकाता, मुर्शिदाबाद जैसे अनेक जनपदों में भूजल में आर्सेनिक का होना सामान्य बात है। इन इलाकों में रहने वाले लोग अधिकांशतः कैंसर, फेफड़े, औरतों की बीमारियां, अस्थमा, त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित रहते हैं। गौरतलब है राज्य सरकार की तरफ से लोगों को साफ और शुद्ध पेय जल मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती है। पेय जल की उपलब्धता और बात है शुद्ध पेय जल उपलब्ध होना अलग बात। इसलिए राज्य सरकार को पेय जल की उपलब्धता के बजाय शुद्ध पेय जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदूषित पानी पीने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिस जानवर को पाला जाता है और खेती के लिए प्रयोग किया जाता है वे सभी जहरीले तत्वों के प्रभाव से ग्रसित हो जाते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों, जानवरों और खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक - रसायन युक्त पानी के इस्तेमाल से फ्लोराइड से फ्लोरोसिस, नाइट्रेट की अधिकता से श्वास संबंधी परेशानियां, कैंसर, लौह एवं लवणयुक्त पानी पीने से ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस और आर्सेनिक युक्त जल पीने से कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यानी यदि भारत के करोड़ों लोगों को शुद्ध साफ पानी मुहैया करा दिया जाए के करोड़ों लोग तमाम खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। नई वैज्ञानिक भूजल शोधन तकनीकों से आर्सेनिक नाइट्रेट और दूसरे जहरीले रसायनों का भूजल में मिश्रित होने की प्रक्रिया को समझकर भूजल को जहरीला होने से रोका जासकता है। उदाहरणार्थ - अपरदन के माध्यम से, चट्टानों में मौजूद खनिज मिट्टी में आर्सेनिक छोड़ते रहते हैं। फिर मिट्टी से यह भूजल में चला जाता है जिससे भूजल जहरीला हो जाता है। इसके अलावा मानव गतिविधियों जैसे खनन और भू तापीय उष्मा उत्पादन, आर्सेनिक के पेयजल मिलने की प्रक्रिया को बढ़ाते है। इसका एक उदाहरण कोयला जलने के बाद उसकी बची हुई राख जिसमें आर्सेनिक एवं दूसरे जहरीले पदार्थ होते है, हवा या दूसरे माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते है। जाते हैं। गौरतलब है भूजल में जहरीले तत्वों के मिश्रण, जिस प्रक्रिया से जल को दूषित करते हैं। उस प्रक्रिया को रोकना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। लेकिन नई तकनीक के इस्तेमाल से जल का शोधन कर पीने लायक पानी लोगों को मुहैया कराया जा सकता है।

पांच साल पहले केंद्र सरकार ने 2024 तक प्रत्येक परिवार को शुद्ध पीने युक्त पानी मुहैया कराने की योजना बनाई थी। हर घर नल योजना के तहत बहुत बड़ी आबादी पीने का शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। लेकिन अब भी बहुत बड़ी आबादी को शुद्ध जल पीने को नहीं मिल रहा है। भूजल के जहरीले होने और भूजल स्तर के लगातार नीचे चले जाने जैसी विकट समस्या के समाधान के बिना देश के प्रत्येक परिवार को कैसे साफ और शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा सकता है। केन्द्र और राज्य सरकारों की हर परिवार तक शुद्ध जल पहुंचाने की योजना को कारगर तरीके से लागू करने की जरूरत है। पाताल के नीचे जल की अशुद्धता को कैसे रोका जायेगा, जबतक पाताल का पानी शुद्ध नहीं होगा। तब तक पीने वाले पानी की समस्या का हल होना नामुमकिन लगता है। पर्यावरण मंत्रालय की मदद से केन्द्रीय एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आई एम आई एस) द्वारा देश में पानी की गुणवत्ता को लेकर तैयार किये गये आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान की 19658 बस्तियां और इसमें रहने वाले 77.75 लाख लोग जहरीले पानी को पीने की वजह से प्रभावित है। आई एम आई एस की यह रिपोर्ट आगे बताती है-कि- पूरे देश में 70740 बस्तियां फ्लोराइड, आर्सेनिक लौह तत्व और नाइट्रेट सहित दूसरे लक्षण एवं भारी धातुओं के मिश्रित जल से प्रभावित हैं। इस जहरीले पानी से सीधे-सीधे 47.46 करोड़ आबादी प्रभावित है। राजस्थान में फ्लोराइड, नाइट्रेट और लवण युक्त भूजल का प्रकोप सर्वाधिक है। राज्य में 5998 बस्तियों के 40.98 लाख लोग फ्लोराइड के 12606 बस्तियों में रहने वाले 28.55 लाख लोग लवणयुक्त पानी के और 1054 बस्तियों के 8.20 लाख लोग नाइट्रेट युक्त पानी के इस्तेमाल के लिए मजबूर हैं। वहीं पर असम के भूजल का बहुत बड़ा हिस्सा आर्सेनिक के मिश्रण की वजह से उपयोग किये जाने के योग्य नहीं रह गया है। एक अन्य आंकड़े के मुताबिक असम की 4518 बस्तियों में रहने वाली 18 लाख की आबादी को आर्सेनिक युक्त पानी पीना पड़ रहा है। इससे कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों और पेट को बीमारियों से लोगों को दो-चार होना पड़ रहा है। पाताल के पानी की अशुद्धता की समस्या वर्षों से बनी हुई है। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पीने लायक शुद्ध पानी मिलना किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत में महज तीस प्रतिशत लोगों को पीने लायक पानी उपलब्ध है। उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल में कई तरह के रासायनिकों के मिश्रण की वजह से शुद्ध पानी की उपलब्धता कठिन होती जा रही है। इस दिशा में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर जल मंत्रालय और राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था लेकिन समस्या दिनों दिन बढ़ी। जा रही है। गुजरात के कच्छ, राजस्थान के कई जिले, पश्चिम बंगाल असम, कर्नाटक, हरियाणा पंजाब, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भुजल मिश्रण की समस्या विकराल होती जा रही है। राजस्थान जहां साल के बारहों महीने पानी की किल्लत बनी रहती है। वहां के भू-जल में कई जहरीले तत्व मिश्रित पाये जाते हैं। गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में लोगों को कई किमी. पैदल चलकर पीने का पानी मिलता है, वह भी रासायनिक तत्वों के मिश्रण से युक्त ।

टाइम यूज सर्वे: एक औसत औरत पर एक औसत मर्द से ज्यादा काम का बोझ

वर्ष-2024 के आंकड़े पर आधारित नेशनल सैंपल सर्वे की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार- हमारे देश में एक औसत औरत हर दिन, एक औसत पुरुष की तुलना में एक बेटा ज्यादा काय करती है। सटीक आंकड़े देखें तो प्रति पुरुष, प्रतिदिन 307 मिनट (पांच घंटे सात मिनट) काम करते है। तो एक औसत महिला प्रतिदिन 367 (6 घंटे और 7 मिनट) काम करती है। अंतर मात्र इतना है कि-पुरुष को अधिकांश काम की कमाई मिलती है, लेकिन महिला के अधिकांश काम की कमाई नहीं होती है। एक औसत पुरुष के 307 मिनट में 251 मिनट का काम पैसे देता है कि उसके सिर्फ 56 मिनट ऐसे काम में लगते हैं जिसकी कमाई नहीं होती, लेकिन महिला की स्थिति ठीक उलटी है। उसके उन 367 मिनट में सिर्फ 62 मिनट में काम से कमाई होती है और 305 मिनट का काम कुछ नहीं की श्रेणी में रह जाता है। यानि सिर्फ इतना कहना ठीक नहीं है कि- आदमी बाहर का काम करता है और महिला घर का। अंदर- बाहर दोनों का काम जोड़ दें तो महिला काम भारी पड़ता है। अभी 2024 के सभी आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन 2019 के आंकड़े देखकर हम कुछ गहराई तक पहुंच सकते हैं। यह कुछ नहीं बाला काम दो श्रेणी में नजर आता है। एक तो घर में रसोई सफाई, कपड़ा धोना, पानी भरने जैसा घर चलाने का काम और दूसरा- बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करना। इन दोनों कामों का बोझ महिला पर प्रत्येक वर्ग के परिवार में देखा जा सकता है। यह एक सामान्य भ्रांति है कि अगर औरत कमाने लग जाए तो यह बोझ घट जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, दर असल 'काम काजी' यानी पैसा कमाने वाली महिला दोनों तरफ से पिसती है। ग्रामीण परिवार में कमाने के लिए, काम करने के बाद भी इन दोनों घरेलू कामों में महिला औसतन 348 मिनट खर्च करती है तो शहरी परिवार में भी 316 मिनट। अगर पुरुष बेरोजगार हो तब भी वह घर के काम में हाथ नहीं बंटाता।

पिछली रिपोर्ट इस भ्रांति का भी खंडन करती है कि औरतें साज श्रृंगार में ज्यादा समय खर्च करती हैं। एक औसत दिन में पुरुष नहाने-धोने-तैयार होने में 74 मिनट लगाते हैं और महिलाएं उससे कम 68 मिनट। खाने-पीने में भी पुरुष महिलाओं से दस मिनट फालतू लेते हैं। गृहिणी को सुस्ताने, आराम करने, बातचीत करने और मनोरंजन के लिए दिन में 113 मिनट मिलते हैं, जबकि पुरुष को 127 मिनट। अब सवाल यह उठता है कि यह कौन तय करता है कि किस काम के लिए पैसा, मिले और किसके लिए नहीं? जाहिर है यह काम के महत्व के आधार पर तय नहीं होता। दफ्तर और फैक्ट्री के काम के बिना तो फिर भी दुनिया चल सकती है लेकिन रसोई और बच्चों की देखभाल के बिना नहीं। पुरुषप्रधान समाज ने अपने फायदे के लिए यह व्यवस्था बना रखी है। तो क्या इस अन्याय को ठीक करने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?

पिछले कुछ वर्षों में अनेक राज्यों में महिलाओं को कुछ पैसा नियमित रूप से देने का चलन निकला है। अलग-अलग नाम से चली इन योजनाओं को पैसा बांटने की खतरनाक प्रवृत्ति के रूप में देखा और दिखाया गया है, लेकिन अगर यह देश पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की मेहनत पर चल रहा है तो राष्ट्र निर्माण में उनके इस योगदान के एवज में उन्हें कुछ भुगतान करने में क्या बुरा है? इसे चुनाव से पहले रिश्वत या भीख की तरह देने की बजाय क्यों नहीं महिलाओं के लिए 'कृतज्ञता निधि' जैसी कोई राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जाती? 8 मार्च को इस महिला दिवस पर देश में विचार क्यों नहीं होता? वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए लेकिन एक आधिकारिक रिपोर्ट ने मेरी इस धारणा की पुष्टि कर दी कि एक औसत औरत एक औसत मर्द से ज्यादा काम करती है।

यह कोई छोटा-मोटा अध्ययन या कोई शौकिया आंकड़ा नहीं है। भारत सरकार ने पिछले 5 साल से आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर टाइम यूज सर्वे करवाना शुरू किया है।

दिन दहाड़े बलात्कार की घटनाएं समाज के माथे पर दाग

महज कानून कड़े कर देने से ही महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध थमने से रहे, जब तक उनका ईमानदारी पूर्वक कड़ाई से पालन न किया जाए । ऐसे मामलों में पुलिस -प्रशासन की भूमिका भी अनेक अवसरों पर संदिग्ध रहती है । पुलिस किस प्रकार ऐसे अनेक मामलों में पीड़िताओं को ही परेशान करके उनके जले पर नमक छिड़कने का कार्य करती है। ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का भय कैसे उत्पन्न होगा और कैसे महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी की उम्मीद की जाए? जरूरत इस बात की महसूस की जाने लगी है कि पुलिस को लैंगिक दृष्टि से संवदेनशील बनाया जाए ताकि पुलिस पीड़ित पक्ष को पर्याप्त संबल प्रदान करे और पीडिताएं अपराधियों के खिलाफ खुलकर खड़ा होने की हिम्मत जुटा सकें, साथ ही जांच एजेंसियों और न्यायिक तंत्र से भी ऐसे मामलों में तत्परता से अपेक्षा की जानी चाहिए । ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए समय की मांग यही है कि सरकारें मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त बनाने के साथ- साथ प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करें कि यदि उनके क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के मामलों में कानून का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सामने आती दिनदहाड़े छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग के समान है और यह कहना असंगत नहीं होगा कि महज कड़े कानून बना देने से ही महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगने वाला। आए दिन देशभर में हो रही इस तरह की घटनाएं हमारी सभ्यता की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलात्कार और छेड़छाड़ के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे भी होते हैं, जिनमें पीड़िता के परिजन, निकट संबंधी या परिचित ही आरोपी होते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों में तो यहां तक कहा जा चुका है कि करीब 97 फीसदी मामलों में महिलाएं अपनों की ही शिकार होती हैं और यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि महिला अपराधों के मामले में पूरी दुनिया की यही तस्वीर है। जहां देश में हर 53 मिनट में एक महिला यौन शोषण की शिकार होती है और हर 28 मिनट में अपहरण का मामला सामने आता है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में प्रत्येक तीन में से एक महिला का कभी न कभी शारीरिक शोषण होता है । दुनिया सें करीब 21 फीसदी महिलाएं शारीरिक मानसिक प्रताड़ना अथवा यौन शोषण व हिंसा की शिकार होती हैं, दक्षिण अफ्रीका में हर छह घंटे में एक महिला को उसके साथी द्वारा ही मौत के घाट उतार दिया जाता है और अमेरिका में भी इसी प्रकार कई महिलाएं हर साल अपने ही परिचितों द्वारा मार दी जाती हैं। जहां तक पीडिताओं को न्याय दिलाने की बात है तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग काफी समय से उठती रही है किन्तु हमारा सिस्टम कछुआ चाल से रेंग रहा है। ऐसे मामलों में कठोरता बरतने के साथ-साथ त्वरित न्याय प्रणाली की भी सख्त जरूरत है ताकि महिला अपराधों पर अंकुश लग सके ।आज अगर समाज में शिक्षा के प्रचार - प्रसार के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध और संवेदनहीनता के मामले बढ़ रहे हैं तो हमें यह जानने के प्रयास करने होंगे कि कमी हमारी शिक्षा प्रणाली में है या कारण कुछ और हैं। ऐसे कृत्यों में लिप्त रहने वाले लोगों की कुटिल मानसिकता के कारणों की पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है, साथ ही सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को लागू करना और छात्रों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना समय की मांग है ताकि युवाओं की नकारात्मक सोच को परिवर्तित करने में मदद मिल सके, जिससे स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सके। दुनिया-भर में प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है जो सही मायनों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक वैश्विक दिवस है।

घूँघट की बगावत

9 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

शबरी से द्रौपदी मुर्मू तक का सफर...

दलित महिलाएँ भारत की आबादी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। लंबे समय से, उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करना पड़ा है। भारत में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आख्यान अक्सर हाशिए के समुदायों की महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज करते हैं, इसके बजाय पुरुष-केंद्रित दृष्टिकोण या प्रमुख जातियों के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दलित महिला नायकों की अनकही कहानियों और पूरे इतिहास में उनके संघर्षों को याद करके, हम इन आख्यानों को समृद्ध कर सकते हैं और संस्थागत भेदभाव का सामना कर सकते हैं जिसे दलित महिलाएँ पीढ़ियों से झेलती आ रही हैं। आज की महिला नेता लचीली और विविधतापूर्ण हैं। वे वैश्विक जलवायु आंदोलन में सबसे आगे हैं, सामाजिक सुरक्षा की वकालत कर रही हैं, संकटों से निपट रही हैं और प्रणालीगत नस्लीय भेदभाव को खत्म करने के लिए काम कर रही हैं। दुनिया भर में, महिला नेता जीवन बदल रही हैं और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की प्रेरणा दे रही हैं।

रामायण में सबरी की कहानी स्वीकृति, निस्वार्थता और बिना शर्त प्यार के विषयों का उदाहरण है, जो कई भजनों और कविताओं को प्रेरित करती है। भक्ति के उदय ने संत निर्मला और सोयराबाई जैसी महार जाति की महिलाओं को पारंपरिक हिंदू मान्यताओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। नांगेली ने कठोर "स्तन कर" का बहादुरी से विरोध किया, जो निचली जाति की महिलाओं को लक्षित करता था जो अपने स्तनों को ढकती थीं। कुइली, एक दलित महिला, जिसने तमिलनाडु में शिवगंगा की रानी वेलु नचियार की सेना का नेतृत्व किया, ने 1780 के आसपास ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक अन्य साहसी दलित योद्धा झलकारीबाई, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति थीं, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में सेवा कर रही थीं। उजीराव, लखनऊ समाज सुधारकों में, सावित्रीबाई फुले दलित शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उभरीं, उन्होंने 1848 में मात्र नौ लड़कियों के साथ एक स्कूल की स्थापना की, जो 1851 तक लगभग 150 महिला छात्राओं वाले तीन स्कूलों तक विस्तारित हो गया।

उन्होंने 1849 में एक स्कूल शुरू करने के लिए अपनी मित्र फातिमा शेख के साथ मिलकर काम किया और 1852 में महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की, साथ ही बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की, जो विधवाओं और हमले के पीड़ितों के लिए प्रसव के लिए एक सुरक्षित स्थान था।

मूवलुर रामिमिथम अम्मैयार ने दमनकारी देवदासी प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, 1936 में इस विषय पर एक तमिल उपन्यास प्रकाशित किया और 1945 में काल्पनिक शृंखला दमयंती बनाई। दक्षायनी वेलायुधन ने 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गई पहली और एकमात्र दलित महिला के रूप में इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र में शांताबाई कांबले, मल्लिका अमर शेख और कुमुद पावड़े जैसी लेखिकाओं ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से दलित नारीवाद को उजागर किया। तमिलनाडु में बामा और पी शिवकामी जैसे लेखकों ने लैंगिक भेदभाव को उत्पीड़न के दोहरे रूप के रूप में सम्बोधित किया। उर्मिला पवार और मीनाक्षी मून जैसी मराठी लेखिकाओं ने महिला आंदोलन के भीतर दलित महिलाओं को सुर्खियों में लाने के लिए काम किया, अपने शोध और व्यक्तिगत कहानियों का उपयोग करके उनके सामने आई कठोर वास्तविकताओं को उजागर किया। चुनौतीपूर्ण व्यवस्था में फंसी दलित महिलाओं को बाहर निकलने के विकल्प प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों में सुधार करना आवश्यक है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आर्थिक विकल्पों के साथ जोड़ना महत्त्वपूर्ण है। महिलाओं को कौशल प्रदान करने और शिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण निवेश आवश्यक है, साथ ही औपचारिक क्षेत्र में नई नौकरियों का सर्जन करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ-साथ रोजगार सर्जन में बाधाओं को कम करना भी आवश्यक है। महिलाओं के लिए अधिक स्थिर-मजदूरी वाली नौकरियाँ सुनिश्चित करना उनके सामाजिक-आर्थिक शोषण का मुकाबला करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। गहरी जड़ें जमाए हुए पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को चुनौती देने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। महिलाओं को निर्णय लेने के अधिकार और शासन में उचित प्रतिनिधित्व के साथ सशक्त बनाया जाना चाहिए। इसलिए, भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्रता से पारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से कार्यक्रमों की देखरेख के लिए सरकारी या सामुदायिक संगठन स्थापित किए जाने चाहिए। दलित महिलाओं को लक्षित नीतियों और पहलों की आवश्यकता है जो विशेष रूप से उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करें। व्यापक स्वास्थ्य नीतियाँ, विशेष रूप से मातृ और बाल स्वास्थ्य पर केंद्रित, महत्त्वपूर्ण हैं। केरल के कुदुम्बश्री मॉडल से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करके ऋण तक पहुँच में सुधार किया जा सकता है। भारत में दलित महिलाओं को इस समय एक महत्त्वपूर्ण मोड़ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें तीन महत्त्वपूर्ण बाधाओं से गुजरना पड़ रहा है: वर्ग, जाति और पितृसत्ता। सामाजिक संरचना के ये तीन परस्पर जुड़े पहलू लैंगिक गतिशीलता और दलित महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न को समझने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

-प्रियंका सौरभ

क्यों नहीं मरा करता वर्तमान से औरंगजेब..!

औरंगजेब जैसे आताताई हिंदुस्तान में मर कर भी जिंदा हो उठते है । इसके पीछे हमारे देश का लचीला संविधान , देश के गद्दार और अभिवायक्ति की आजादी है जो देश के उन गद्दारों, उन सपोलो को फन उठाने का मौका दे देती है जिनके रगों में ऐसे आतंकियों का लहू बह रहा । एक बड़ा वर्ग एक ओर जहां इस बात को मानकर गदगद है कि भारत में हिन्दू राष्ट्र की स्थापना हो चुकी है क्योंकि लगभग एक हजार वर्षों के बाद कोई हिन्दू शासक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा है, तो वहीं उसे यह देखकर दुःख भी होता है कि देश के सियासी गलियारे में अब भी मुगलिया शासकों की उपस्थिति बनी हुई है। 2014 के बाद से यह विमर्श सघन तो हुआ ही, बहुस्तरीय भी बन गया। एक तरफ भाजपा ने खुद को हिन्दुओं की पार्टी बना डाला तो वहीं सरकार ऐसे कानून बनाने लग गयी जिसके निशाने पर किसी न किसी तरह से कट्टर कौम ही होते हैं। फिर चाहे वह नागरिकता कानून हों या जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, तीन तलाक का खात्मा या वक्फ बोर्ड में बदलाव। अखिलेश और राहुल चुनावी सभाओं से लेकर संसद के भीतर अपने भाषणों में मुस्लिम समर्थन के सूत्रधार बने हुए हैं। ताज्जुब है कि अबू आजमी तो ठीक पर अखिलेश और राहुल जैसे देश को नफरत की आग में झोंकने और वोट की भूख को हवा देने के लिये बाबर से शुरू कर भारतीय राजनीति को इन दिनों औरंगजेब पर धकेल रहे है। सवाल यह है कि इस कथित 'जल्लाद' और 'हिन्दू विरोधी' के बाद किस शासक का नम्बर आयेगा क्योंकि औरंगजेब के बाद से मुगलिया सल्तनत लगातार कमजोर हो चली थी जो बहादुरशाह जफर के साथ पूरी तरह खत्म हो गयी? औरंगजेब से जफर के बीच कोई भी उल्लेखनीय बादशाह तो हुआ नहीं। हुए भी तो इतने कमजोर कि उनके नाम भी किसी को मालूम नहीं। 1991 में देश की राजनीति में बाबर का प्रवेश गाजे-बाजे के साथ भाजपा द्वारा किया गया- अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर को मुद्दा बनाकर। देश में मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा इसे तुड़वाकर (1528-29) बाबरी मस्जिद बनवाई गयी थी। इसे लेकर भाजपा का राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ। लालकृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से लेकर निकली रथयात्रा ने देश की राजनीति का विमर्श कुछ यूं बदला कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 3 बार (क्रमशः 13 दिन, 13 माह व पूर्णकालिक) सरकारें बनीं। इस दौरान किसी को बाबर याद नहीं आया। शुक्र है कि मुगलों के जने रोहिंज्ञाओं की झोपड़पट्टियों में जीवन बिता रहे हैं, वरना वे भी आज आलोचना के केन्द्र में होते- धुव्रीकरण के उपकरण के रूप में। वैसे तो मुस्लिमों को लेकर होने वाली सियासत का दौर आजादी के पहले से ही शुरू हो गया था पर इसे सही रूप दिया मुलायम और अखिलेश यादव के सपा ने । 2014 के बाद, यानी नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में नेहरू-मुसलमान सम्बन्धों की पुस्तक में नया अध्याय यह जुड़ गया कि नेहरू के पुरखे मुसलमान थे। यानी वे ऐसे परिवार से हैं जो पहले मुस्लिम था। सोशल मीडिया के आईटी सेल द्वारा रचित एवं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के जरिये लोगों को ज्ञात हुआ कुछ कौमी वंश किसी गियासुद्दीन गाजी से सम्बद्ध है। जिस देश में ज्यादातर हिन्दुओं की कई पुश्तों का विवरण प्रयागराज और हरिद्वार में उन घाटों के पंडितों के सैकड़ों वर्षों से लिखे जा रहे बही-खातों में दर्ज हैं जहां पितरों का अस्थि विसर्जन होता है, देश के लोगों ने नेहरू के मुस्लिम कनेक्शन को सच मान लिया। इंदिरा गांधी के पारसी पति फिरोजशाह को भी मुस्लिम साबित करने में कोई दिक्कत नहीं आई। चूंकि राहुल व प्रियंका की मां सोनिया ईसाई परिवार से आती हैं तो इस तड़के में एक और जायका मिलाकर विमर्श आगे बढ़ा जिसके कई आयाम खुलते हैं। कभी-कभार इसका उल्लेख इन शब्दों में ही होता था कि 'काबुल में उसके मकबरे पर कोई नहीं जाता पर भारत में उसकी पूछ-परख बनी हुई है।' इस तंज के निशाने पर कांग्रेस होती थी। संविधान की भावना के अनुरूप अल्पसंख्यकों की सरकार की ओर से देखरेख को 'तुष्टिकरण' बतलाया जाता रहा। किसी किताब को हाथ भी न लगाने वालों को वर्षों पहले नालंदा विश्वविद्यालय के जलाये जाने का दुःख अब जाकर साल रहा है। इसी के तहत फि लहाल भारत की राजनीति में औरंगजेब तहलका मचाये हुए हैं। दो साल पुराना एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक युवा सार्वजनिक शौचालय में औरंगजेब की तस्वीर चस्पां कर रहा है तो वहीं मुम्बई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर हो रही है क्योंकि वे औरंगजेब की शासन प्रणाली की तारीफ कर देते हैं जो की उनके गद्दार होने की बात दशार्ती है । उन्होंने चाहे

अपना बयान वापस ले लिया हो लेकिन उन्हें विधानसभा के जारी बजट सत्र से निलम्बित कर दिया गया है। राजद्रोह का मामला चलाने की मांग भी हो रही है। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना का गुस्सा, अकबर के हरम के किस्से, शाहजहां द्वारा कथित रूप से तेजोमहालय मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनाने के आरोपों के बाद औरंगजेब भी निपट गये हैं।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर यूपी

मोटापे को निमंत्रण देती बदलती जीवनशैली

भारत में मोटापे में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, रिपोर्ट में बताया गया है कि 24% पुरुष और 25% महिलाएँ अब अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। चिंताजनक रूप से, पिछले एक दशक में 5-9 वर्ष की आयु के बच्चों में मोटापा दोगुना हो गया है। शहरीकरण, आहार में बदलाव, गतिहीन आदतें और पर्यावरणीय प्रभाव जैसे कारक इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त महिलाओं का प्रतिशत 20.6% से बढ़कर 24% हो गया, जबकि पुरुषों के लिए यह 18.9% से बढ़कर 22.9% हो गया है। इसके अलावा, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की दर 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गई है और बड़े बच्चों में यह रुझान और भी खराब है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 का अनुमान है कि 2030 तक 5-9 वर्ष की आयु के 10.81% बच्चे और 10-19 वर्ष की आयु के 6.23% बच्चे मोटे होंगे। द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथईस्ट एशिया के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में लगभग 40% महिलाएँ और 12% पुरुष उदर मोटापे से पीड़ित हैं। आनुवंशिक कारक उदर क्षेत्र में वसा जमा होने की प्रवृत्ति में योगदान करते हैं, जिससे चयापचय सम्बंधी विकारों का खतरा बढ़ जाता है। जबकि मोटापा मुख्य रूप से शहरी समस्या है, लेकिन जीवनशैली में बदलाव और आहार सम्बंधी आदतों के कारण यह ग्रामीण आबादी को तेजी से प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में, भारत में 60% मौतें गैर-संचारी रोगों के कारण होती हैं, जो मोटापे और निष्क्रिय जीवनशैली के कारण और भी गंभीर हो जाती हैं।

अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें, अत्यधिक प्रस-ंस्कृत खाद्य पदार्थों, परिष्कृत शर्करा और चिकना फ-ास्ट फूड का बढ़ता सेवन मोटापे की बढ़ती दरों का एक प्रमुख कारक है। भारतीय शहरों में फास्ट-फूड के चलन ने विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग की आबादी को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप मोटापे के स्तर में वृद्धि हुई है। प्रोटीन, डेयरी और फलों की उच्च कीमतों के कारण कई कम आय वाले परिवार चावल और गेहूँ जैसे सस्ते, उच्च काबोहाइड्रेट वाले आहार की ओर रुख करते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मुख्य रूप से मुख्य अनाज की आपूर्ति करती है, जिसमें संतुलित आहार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों की कमी होती है। डिजिटल मनोरंजन और लंबे समय तक काम करने के साथ-साथ बैठे-बैठे ऑफिस की नौकरी, शारीरिक गतिविधि के लिए बहुत कम समय देती है, जिससे वजन बढ़ता है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार, 50% भारतीय पर्याप्त शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, जो मोटापे की महामारी का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। पोषण और व्यायाम के बारे में जागरूकता की कमी के कारण जीवनशैली के गलत विकल्प चुने जाते हैं, खास तौर पर निम्न आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों में। कई भारतीय परिवार गलती से अधिक वजन को अच्छे स्वास्थ्य का संकेत मान लेते हैं, जिससे मोटापे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप में देरी होती है। खास तौर पर बच्चों के बीच प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, शर्करा युक्त पेय पदार्थों और फास्ट फूड का आक्रामक विपणन आहार विकल्पों को बहुत प्रभावित करता है। सोशल मीडिया प्रचार और सेलिब्रिटी समर्थन युवाओं में जंक फूड की खपत को और बढ़ावा देते हैं। शहरी क्षेत्रों के विस्तार के साथ-साथ डिजिटल मनोरंजन और दूर से काम करने के प्रचलन ने समग्र शारीरिक गतिविधि के स्तर को कम कर दिया है। यातायात की भीड़ और प्रदूषण बाहरी व्यायाम को रोकते हैं, जिससे गतिहीन इनडोर गतिविधियों पर अधिक निर्भरता होती है। पार्क, खेल के मैदान और पैदल चलने वालों के अनुकूल क्षेत्रों की कमी से पैदल चलना और साइकिल चलाना जैसी शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना मुश्किल हो जाता है। खराब शहरी नियोजन और साइकिल चलाने के बुनियादी ढांचे की कमी सक्रिय आवागमन को जटिल बनाती है, जिससे मोटापे की दर बढ़ती है। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण से सम्बंधित सूजन चयापचय सम्बंधी विकारों के जोखिम को बढ़ाती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। शोध से पता चला है कि भारतीय शहरों में उच्च प्रदूषण स्तर और आंत की चर्बी के संचय और मोटापे में वृद्धि के बीच सम्बंध है। फास्ट-फूड श्रृंखलाओं और प्रसंस्कृत खाद्य बाजारों के अनियंत्रित विस्तार के कारण, विशेष रूप से शहरी केंद्रों में, ताजे उत्पादों की तुलना में अस्वास्थ्यकर विकल्प अधिक सुलभ हो गए हैं।

मोटापे को दूर करना एक तत्काल प्राथमिकता है। हमें स्वस्थ भोजन विकल्पों के लिए सब्सिडी प्रदान करते हुए शर्करा युक्त पेय पदार्थों और अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर उच्च कर लागू करने पर विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, मेक्सिको के चीनी कर के परिणामस्वरूप शीतल पेय की खपत में 12% की कमी आई, जो मोटापे से निपटने में इसकी प्रभावशीलता को दशार्ता है। इसके अतिरिक्त, स्कूलों और कार्यस्थलों में अनिवार्य शारीरिक शिक्षा और पोषण शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक है। जापान की 'शोकुइकु' पहल ने संतुलित आहार पर जोर देकर बचपन के मोटापे की दर को सफलतापूर्वक कम किया है। पैदल यात्री-अनुकूल सड़कें, साइकिल पथ और सुरक्षित सार्वजनिक पार्क बनाना दैनिक शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकता है। नीदरलैंड के शहरी साइकिल चालन दृष्टिकोण ने सक्रिय आवागमन के माध्यम से मोटापे की दर में कमी दिखाई है। पैकेज्ड सामानों पर स्पष्ट खाद्य लेबलिंग भी उपभोक्ताओं को सूचित आहार सम्बंधी निर्णय लेने में मदद करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। उच्च चीनी और उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों पर चिली के फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल ने बच्चों के बीच जंक फूड की खपत को सफलतापूर्वक कम किया है।

संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कम चीनी सेवन को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय अभियान उपभोक्ता व्यवहार को बदलने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। फिट इंडिया मूवमेंट और ईट राइट इंडिया अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य आबादी के बीच स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों को बढ़ावा देना है। एक स्वस्थ राष्ट्र वास्तव में एक समृद्ध राष्ट्र होता है। मोटापे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, हमें एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों को मजबूत करे, पौष्टिक भोजन को प्रोत्साहित करे, शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करे और सुनिश्चित करे कि शहरी नियोजन सक्रिय जीवन का समर्थन करे। पोषण अभियान और ईट राइट इंडिया जैसी पहलों को सामुदाय-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधानों के साथ विस्तारित करने से स्थायी परिवर्तन होगा।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

अपनी मंज़िल के लिए अपनी राहें चुनती महिलाएं

पिछले दस वर्षों में, युवा भारतीय महिलाओं के लक्ष्यों और महत्त्व-ाकांक्षाओं में उल्लेखनीय बदलाव आया है, जो उनकी बढ़ती स्वतंत्रता, शैक्षिक उपलब्धियों और कार्यबल में भागीदारी को दशार्ता है। यह बदलाव भारत के सामाजिक ताने-बाने को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल रहा है। आज, लड़कियाँ उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लड़कों के बराबर शैक्षिक स्तर प्राप्त कर रही हैं, जिसमें 50% से अधिक कक्षा 12 पूरी कर रही हैं और 26% ने कॉलेज की डिग्री हासिल की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन की बढ़ती प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है, जिसमें महिला सकल नामांकन अनुपात 27.3% तक बढ़ गया है। युवा महिलाएँ अब अपने पेशेवर लक्ष्यों पर अधिक जोर दे रही हैं, जो विभिन्न कैरियर अवसरों और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण तक पहुँच से प्रेरित है। स्किल इंडिया मिशन और एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) फॉर गर्ल्स इंडिया जैसी पहलों ने तकनीकी क्षेत्रों में युवा महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया है। विवाह की औसत आयु 2005 में 18.3 वर्ष से बढ़कर 2021 में 22 वर्ष हो गई है, जिसमें कई युवा महिलाएँ अनुकूलता के आधार पर साथी चुन रही हैं।

एक रिपोर्ट बताती है कि अब 52% महिलाओं को अपने साथी चुनने का अधिकार है, जो 2012 में 42% से अधिक है। कई महिलाएँ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त कर रही हैं, विशेष रूप से उद्यमिता के माध्यम से, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए सरकारी पहलों द्वारा समर्थित है। उदाहरण के लिए, नीति आयोग द्वारा महिला उद्यमिता मंच ने 10,000 से अधिक महिला उद्यमियों का एक नेटवर्क बनाया है। युवा महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय शासन में अधिक भागीदारी के साथ, राजनीति में अधिक सक्रिय हो रही हैं। ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता 2012 में 10% से बढ़कर 2022 में 18% होने की उम्मीद है। ये उभरती हुई आकांक्षाएँ पारंपरिक सामाजिक मानदंडों और संरचनाओं को चुनौती दे रही हैं। जैसे-जैसे अधिक महिलाएँ कार्यबल में प्रवेश कर रही हैं, घरों में पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ बदल रही हैं। मनरेगा कार्यक्रम पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है, जो ग्रामीण परिवार की गतिशीलता को प्रभावित करता है। शिक्षा और आय में वृद्धि के साथ, युवा महिलाएँ अपने परिवारों के भीतर वित्तीय और सामाजिक निर्णयों पर अधिक प्रभाव प्राप्त कर रही हैं। स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं को घरेलू वित्त का सामूहिक रूप से प्रबंधन करने के लिए सशक्त बनाया है।

आज, लड़कियाँ उच्च शिक्षा और कौशल विकास में लड़कों के बराबर शैक्षिक उपलब्धियाँ हासिल कर रही हैं, 50% से अधिक युवतियाँ कक्षा 12 तक की पढ़ाई पूरी कर रही हैं और 26% कॉलेज की डिग्री प्राप्त कर रही हैं। युवा महिलाएँ विभिन्न प्रकार के करियर विकल्पों और डिजिटल कौशल प्लेटफॉर्म की उपलब्धता से प्रेरित होकर पेशेवर योग्यता पर अधिक जोर दे रही हैं। स्किल इंडिया मिशन और एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) फॉर गर्ल्स इंडिया जैसी पहलों ने तकनीकी विषयों में युवा महिलाओं की भागीदारी को काफी हद तक बढ़ा दिया है। आज महिलाओं को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आजादी मिली हुई है। सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर वे अपने भविष्य की ज़िम्मेदारी खुद उठा रही हैं। कई तरह के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, महिलाएँ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रही हैं।

भारतीय महिलाएँ ऊर्जा, दूरदर्शिता, जीवंतता और चुनौतियों पर विजय पाने की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। जैसा कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने खूबसूरती से व्यक्त किया है, महिलाएँ सिर्फ.घर की रोशनी ही नहीं हैं, बल्कि उस रोशनी को जलाने वाली लौ भी हैं। पूरे इतिहास में, महिलाओं ने मानवता को प्रेरित किया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले तक, जिन्होंने समाज में परिवर्तनकारी बदलाव का उदाहरण पेश किया है। भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना है। इन लक्ष्यों का एक प्रमुख लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना है। वर्तमान में, प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं के अंतर्निहित नेतृत्व गुण समाज के लिए अमूल्य हैं। जैसा कि अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने समझदारी से कहा था, एक पुरुष को शिक्षित करने से एक व्यक्ति को लाभ होता है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से पूरी पीढ़ी को लाभ होता है। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से, महिलाएँ न केवल खुद को ऊपर उठा रही हैं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं।

सरकार से मिल रही निरंतर वित्तीय सहायता के साथ, आत्मनिर्भर भारत पहल में उनकी भूमिका प्रतिदिन बढ़ रही है। पिछले 6-7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों के आंदोलन ने महत्त्वपूर्ण गति पकड़ी है, जिसके साथ अब पूरे देश में 7 मिलियन समूह सक्रिय हैं। महिलाओं की ताकत को पहचानना हमें उपलब्धि की नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। आइए उनकी प्रगति और सफलता का समर्थन करें। 'अमृत काल' महिलाओं के व्यापक सशक्तिकरण के लिए समर्पित समय हो। युवा भारतीय महिलाओं की बढ़ती आकांक्षाएँ भारत के सामाजिक परिदृश्य को नया आकार दे रही हैं, एक ऐसे समाज का निर्माण कर रही हैं जहाँ लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण मानक हैं। सहायक नीतियों को लागू करने से इस परिवर्तन में और तेजी आ सकती है, जिससे अधिक समावेशी और सशक्त भविष्य बन सकता है। आज महिलाओं को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आजादी मिली हुई है। सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर वे अपने भविष्य की ज़िम्मेदारी खुद उठा रही हैं। कई तरह के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, महिलाएँ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर रही हैं। उन्हें अब कमजोर लिंग के रूप में नहीं देखा जाता। समान अवसर दिए जाने पर, महिलाएँ अपना रास्ता खुद तय कर सकती हैं। हालाँकि, इन अवसरों तक पहुँचना एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

जब महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, तो वे किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती हैं। समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में प्रत्येक व्यक्ति की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। चूँकि समाज व्यक्तियों से बना होता है, इसलिए हर स्तर पर सामूहिक प्रयास सार्थक बदलाव ला सकते हैं। जब हर कोई महिलाओं का सम्मान करना शुरू कर देगा, तो समग्र स्थिति में सुधार होगा।

प्रियंका सौरभ

क्यों लोग लाज ,मर्यादा , हया
का लिबास हम पर ही लादा गया
संस्कारों, जिम्मेदारियों का मांग
टीका हमारे सर ही नवाजा गया
जब उठे ये सवाल मेरे जहन में तो,
जवाब देने खुद मेरे सवाल आया
मिला के मेरी नजरों से नजरे मेरे सवालों ने
मुझे हाय,बेचारी नारी के चंगुल से बाहर लाया
बोले मेरे सवाल की इन सवालों का
तू खुद ही है जवाब
जिन लोग- लाज ,संस्कारों, जिम्मेदारियों की,
तू कर रही है बात
नहीं है इन मर्दों के कंधों में
इतनी जान जो सम्भाल सके ,
ये बेशकीमती लिबास
इसी लिए तुझे नवाजा है
खुदा ने अनेकों शक्तियों से
जहां एक ओर,ममता, करुणा,
भावनाओं का समंदर बहता है तेरे भीतर
वहीं लड़ जाती है बन के काली
जब बात आए तेरे स्वाभिमान पर
अब सुलझ गए थे मेरे सारे सवाल
होने पर एक नारी खुद पे हुआ अभिमान !

नीतू यादव
जयपुर (राजस्थान)

आजादी, समानता और सम्मान: महिलाओं का संघर्ष

भारत में भी महिला संघर्ष की विकसित होती हुई परंपरा को हम देख सकते हैं। आजादी के पहले चाहे 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम हो या आजादी का सवाल और उससे जुड़ा छात्र, मजदूर, किसान आंदोलन, महिलाओं ने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है तथा अपने ऐतिहासिक दायित्व को पूरा करने में अपनी सीमा को तोड़ा है। इस दौर में महिलाओं ने न सिर्फ देश की आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि सदियों की रूढ़ियों व बंधनों के खिलाफ अपनी इज्जत, समानता, न्याय व प्रतिष्ठा जैसे मानवीय मूल्यों के लिए भी संघर्ष किया महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आम महिलाओं ने जिस बहादुराना संघर्ष का परिचय दिया, तरह महिला आंदोलन का मुख्य चरित्र वर्तमान व्यवस्था विरोधी है।

यहां यह भी घ्यान देने योग्य है कि महिलाओं को न सिर्फ अपनी विशेष समस्याओं से गुजरना पड़ता है बल्कि उन्हें समाज की आम समस्याओं जैसे शोषण, महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि से भी गुजरना पड़ता है। महिलाओं की आम समस्या जनता के विभिन्न तबकों की आम समस्याओं का ही हिस्सा है और इन तमाम समस्याओं की जड़ वर्तमान व्यवस्था में ही निहित है। वर्तमान महिला आंदोलन, व्यवस्था विरोधी आंदोलन के साथ ही जनवादी आंदोलन का अभिन्न अंग है। आज के जन आंदोलन में महिला

वह किसी से छिपा नहीं है। बीसवीं सदी के तमाम महत्वपूर्ण आंदोलनों और संघर्षों में भी उनकी भूमिका रही है। रेल, कपड़ा आदि उद्योग की हड़ताल, राष्ट्रीय आंदोलन, तेलंगाना का किसान आंदोलन, महाराष्ट्र और पंजाब का किसान आंदोलन आदि इसके अनगिनत उदाहरण हैं।

इस 21वीं सदी में भी आजादी, सम्मान और समानता के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी है। आज भी जहां और जब महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता हैं, महिलाएं सड़कों पर आदोलनरत दिखती है। निर्भया को लेकर जो आदोलन चला, उसी की देन है कि सरकार को भी जे सी वर्मा आयोग का गठन करना पड़ा और इस दिशा में कानून बनाने को वह बाध्य हुई। आज भी पितृसत्तात्मक व मनुवादी प्रवृतियां हावी हो रही है। महिला हिंसा आम बात हो गयी है। ऐसे में महिला आंदोलन आज के समय का जरूरी आन्दोलन बनकर उभरा है। स्वतंत्रता, समानता और इंसाफ की लड़ाई तेज हुई है। महिलाएं न सिर्फ सामंती जकड़न के खिलाफ संघर्ष के मैदान में हैं बल्कि महिला हिंसा और मौजूदा सरकार के सांप्रदायिक विभाजन की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। महिलाओं के मुद्दे सिर्फ महिलाओं के नहीं पूरे समाज के हैं। कोई भी बुद्धिमान और सजग व्यक्ति समझ सकता है कि समस्याओं की जड़ वर्तमान व्यवस्था में निहित है। वर्तमान व्यवस्था ही महिला विरोधी मूल्यों को संरक्षण करती है तथा संविधान में समानता का अधिकार देने के बाद भी इस मूल्य-व्यवस्था को जिंदा रखा है। इस

आंदोलन अपनी अलग पहचान रखने के बावजूद वह जनता के विभिन्न तबकों जैसे छात्र, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मध्यवर्ग आदि के आंदोलन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि महिलाएं अपनी विशिष्ट समस्या के लिए महिला आंदोलन में संगठित हों, वहीं महिला आंदोलन अपनी व्यापकता और विकास के लिए विराट जन आंदोलन से गहराई से जुड़े और उस-का हिस्सा बने। रचना और विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसी भी देश या राज्य या दुनिया की घटनाओं का असर महिलाओं पर भी पड़ता है। जब भी किसी देश के शासक वर्ग ने शोषण और उत्पीडन का चक्र चलाया है, महिलाएं उससे अछूती नहीं रही हैं। यहीं नहीं जब भी दुनिया में न्याय, आजादी और जनतंत्र का संघर्ष तेज हुआ है, महिलाएं उस संघर्ष के अभिन्न अंग के रूप में सामने आई है। उन्होंने पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाया है। चाहे वह अमेरिका हो या रूस व वियतनाम हो या ईरान व पाकिस्तान या भारत हो, महिलाओं ने अन्याय, तानाशाही, दमन आदि के खिलाफ अपने मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। हमारे देश में सीएए के विरोध में 'शाहीनबाग' में जो आंदोलन चला, उसकी मुख्य कर्ताधर्ता महिलाएं थीं। वे दादियां' चर्चा में रहीं। उन्हें इस आंदोलन के लिए सम्मानित भी किया गया। उम्र उनके रास्ते में बाधा नहीं है। दादियां हों या युवा लड़कियां आंदोलनों में उदाहरण बनकर उभरी हैं।

पिछले दिनों किसानों का जो आंदोलन चला, उसमें भी महिलाओं की पूरी सहभागिता रही है। उन्होंने पुरुष किसानों के साथ कदम से कदम मिलाया।

इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए संघर्ष किया। 8 मार्च 1857 को अमेरिका के कपड़ा उद्योग में काम करने वाली महिला मजदूरों ने अपने काम के घंटे 16 से कम करके 10 घंटे करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। दुनिया में यह पहली घटना थी जब महिलाएं संगठित होकर संघर्ष करने के लिए आगे आई थीं। 1910 में संपन्न समाजवादी महिलाओं

की अंतरराष्ट्रीय परिषद में क्रांतिकारी महिला नेता क्लारा जेटकिन ने यह प्रस्ताव रखा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया जाए। प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव का उत्साह पूर्वक समर्थन किया। तभी से दुनिया की महिलाएं इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाती हैं। इस दिन का महिला संघर्ष के लिए वही महत्व है, जो मजदूरों के लिए मई दिवस का है। इसे अंतराष्ट्रीय दिवस की अंतर्वस्तु में महिलाओं के संघर्ष और कुबार्नी का इतिहास छिपा है। 917 में सोवियत रूस में समाजवादी क्रांति हुई थी। इस क्रांति में महिलाओं की गौरवमयी भूमिका रही है। 1937 में जनरल फ्रैको की दमनकारी सत्ता के खिलाफ स्पेन में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, वहीं 1943 में इतालवी महिलाओं ने मुसोलिनी की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन चलाया। पिछली शताब्दी के आठवें दशक के पूर्वार्ध में अमरीकी साम्राज्यवाद से राष्ट्रीय मुक्ति के लिए वियतनामी महिलाओं ने दुनिया में घूम-घूम कर अमरीकी साम्राज्यवाद के खिलाफ विश्व जनमत तैयार किया बल्कि हाथों में बंदूक लेकर उन्होंने साम्राज्यवादियों का मुकाबला किया। मादाम विन्ह जैसी नेता इसी संघर्ष से पैदा हुईं। 1979 में, ईरान में नारी मुक्ति आंदोलन की नींव डाली गई। वहां के दकियानूसी रिवाज व सरकार के कानून का विरोध करते हुए पांच हजार महिलाओं ने प्रदर्शन किया और मजबूर होकर सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा।

कादम्बिनी बोस गांगुली: पहली महिला स्नातक

शिक्षा का महत्व हर युग में था, है और रहेगा। यह बात तो सभी जानते और मानते हैं, लेकिन विगत के दशकों में उच्च शिक्षा पर पुरुषों का जो करीब-करीब एकाधिकार था उसे मिथ्या साबित किया देश की पहली स्नातक महिला कादम्बिनी बोस गांगुली ने। बंगाली परिवार में जन्मीं कादम्बिनी बोस गांगुली को देश की पहली महिला स्नातक होने का सौभाग्य प्राप्त है। गांगुली ने उन दिनों उच्च शिक्षा हासिल की जिन दिनों लड़कियां प्राथमिक शिक्षा भी बमुश्किल प्राप्त कर पाती थीं।

कार्दबिनी का जन्म बंगाली पुनर्जागरण के दौरान 18 जुलाई, 1861 को भागलपुर में हुआ था। उनके पिता हिंदू-सुधार आंदोलन बह्म-समाज के एक प्रभावशाली सदस्य थे। कादम्बिनी के पिता भागलपुर स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उन्होंने परिवार और समाज से कादम्बिनी को स्कूल जाने की अनुमति दी थी। 1882 में कादम्बिनी गांगुली ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री (बीए) की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी औपचारिक डिग्री 1883 में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान सौंपी गई कादम्बिनी ने प्राथमिक शिक्षा के बाद भारत के पहले महिला महाविद्यालय में प्रवेश लिया, जिसका वाद में बेथ्यून कॉलेज में विलय हो गया। कादम्बिनी की सफलता ने बेथ्यून कॉलेज को अपना एफए (फाइन आर्ट्स) कार्यक्रम शुरू करने और स्नातक पाठ्यक्रम खोलने के लिए प्रेरित किया। पहली कक्षाओं में केवल दो छात्राएं थीं कादम्बिनी और उनकी सहपाठी चंद्रमुखी बस। स्नातक के बाद कादबिनी ने बेथ्यून कॉलेज में अपने गुरु और शिक्षक द्वारकानाथ गागुली से विवाह किया । भारत के महिला अधिकार आदोलन के नेता द्वाराकानाथ ने अपनी पत्नी को मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कादम्बिनी को प्रवेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन दंपति ने लड़ाई लड़ी और अंततः उन्हें अपनी पहली महिला मेडिकल छात्रा के रूप में भर्ती किया गया। शिक्षकों और कर्मचारियों के लगातार विरोध के बावजूद कादबिनी ने 1886 में कलकत्ता से बंगाल मेडिकल कॉलेज की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पहली भारतीय-शिक्षित महिला डॉक्टर बन गई। उन्होंने 1892 में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की। भारत लौटने पर लेडी डफरिन अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम किया।

ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली
पहली भारतीय महिता एस. विजयलक्ष्मी

हौसले बुलंद हो तो कामयाबी अवश्य मिलती है, इस कथन को और पुख्ता किया एस. विजयलक्ष्मी की लगन ने। विश्व शतरंज (चेस) प्रतियोगिता में जीत हासिल करना तो बड़ी बात है ही उससे भी बड़ी बात यह है कि जीत का सेहरा एक महिला के सिर बंधा। एस. विजयलक्ष्मी देश की पहली ऐसी महिला हैं, जिससे नाम के साथ ग्रैंडमास्टर की उपाधि दी जाती है। शतरंज को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है। हर वर्ष वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विश्व स्तर पर शतरंज प्रतियोगिता कराई जाती है और विजेता को ग्रैंडमास्टर की उपाधि दी जाती है। वैसे तो अब तक अनेक भारतीय इस उपाधि के हकदार हो चुके हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण उपाधि को हसिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी का नाम है- एस. विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी ने शह और मात के इस खेल में बाजी मारते हुए 24 जुलाई 2000 में इतिहास रचा और देश की पहली महिला ग्रैंडमास्टर बनीं। विजयलक्ष्मी का जन्म 25 मार्च 1979 में चेन्नई में हुआ था। वे बचपन से ही शतरंज खेलने लगीं थीं। उम्दा खेल की वजह से उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले जीते। साल 2000 में विजयलक्ष्मी ने विश्व स्तर की शतरंज प्रतियोगिता जीतकर अपने नाम के साथ ग्रैंडमास्टर जोड़ा । विजयलक्ष्मी को इस खेल की प्रेरणा उनके पिता से मिली। उन्हीं के साथ विजयलक्ष्मी ने शतरंज खेलना सीखा। विजयलक्ष्मी ने साल 1986 के ताल शतरंज ओपन से अपनी नई पारी की शुरूआत की थी। इसके बाद साल 1988 और 1989 में अंडर-9 लडकियों के वर्ग में भारतीय चैम्पियनशिप जीती। इतना ही नहीं अंडर-12 की श्रेणी में विजयलक्ष्मी ने 2 बार जीत का खिताब अपने नाम किया। साल 1995 में उन्होंने क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां वो दूसरे स्थान पर रहीं। 2000 में ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल करने वाली पहली भारतीय बनीं। वह इंटरनेशनल मास्टर बनने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी हैं। 2006 में कलमरिया में उन्होंने ग्रैंडमास्टर मानदंड हासिल किया और 2007 में कटरो में अपनी जीत के लिए भी खूब वाहवाही बटोरी।

भारतीयता की तहजीब को आवाज देने वाले फनकार

रूमानियत, समाज एवं संस्कृति में रची बसी जिनकी शायरी हर उम्र के लोगों के जीवन का हिस्सा है, ऐसे महान ह्यशायर-ए-जमालह्ल-सौन्दर्य का कवि कहलाने वाले फिराक गोरखपुरी उर्दू शायरी का देश एवं दुनिया का एक फनकार हैं जिसका रचना-संसार जीते-जी ही नहीं, मरकर भी गूंज रहा है। गोरखपुर को जिन वजहों से दुनिया भर में पहचान मिली, फिराक गोरखपुरी को हमें उनमें आगे की पंक्ति में रखना ही होगा। नाम के आगे गोरखपुरी लगाकर उन्होंने उर्दू अदब की दुनिया में गोरखपुर को जो ऊंचाई दी, गोरखपुर ही नहीं बल्कि समूचे पूर्वांचल के लोग इसके लिए गौरव का अनुभव करते हैं। शायरी कहने के अपने अलमस्त और बेलौस अंदाज को लेकर वह शायरों में ही नहीं, आमजन के बीच भी हमेशा चर्चा का विषय रहे। गंगा-जमुना के संगम एवं सांझी संस्कृति वाले शहर इलाहाबाद के फिराक की तमाम शायरी कुछ ऐसी है जो सही मायने में गंगा-जमुनी तहजीब की शायरी है। और भी कुछ शायर गंगा-जमुनी के तहजीब के माने-कहे जाते हैं लेकिन फिराक के लिए इसका मायने बहुत गहरे एवं हिन्दुस्तान की अस्मिता से जुड़ा था। वे जो लिख रहे थे, असल में हजारों साल की तहजीब को आवाज दे रहे थे, विविधता और विस्तार में एकता की गहरी जड़ें तलाश रहे थे।

रघुपति सहाय से फिराक गोरखपुरी बने, वे भारत के एक प्रसिद्ध उर्दू शायर, कवि, लेखक और आलोचक थे। उनकी साहित्यिक प्रतिभा कविता, गजल, नज्म और निबंध सहित विभिन्न शैलियों में फैली हुई है। प्रगतिशील लेखक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व, गोरखपुरी की रचनाओं में मानवीय भावनाओं, सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक मुद्दों की गहरी समझ झलकती है। उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति ने शास्त्रीय लालित्य को आधुनिक संवेदनाओं के साथ जोड़ा, जिन्होंने शायरी को लोक बोलियों से जोड़कर उसमें नई लोच, नई रंगत, नई ऊर्जा एवं नये मानक उत्पन्न किये। उन्हें फारसी, हिन्दी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ थी, इन्हीं कारणों से उनकी शायरी में भारत की विविधताओं युक्त सांझी रची-बसी हुई है। वे जन-कवि और सौन्दर्य के परम उपासक के रूप में असंख्य लोगों के दिल और दिमाग में रचे-बसे हैं। वैसे भी फिराक के दौर को देखा जाए तो उस वक्त हर तरफ कद्दावर लोग थे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला

फिराक को शायरी की प्रेरणा पिता मुंशी गोरख प्रसाद से भी मिली। बचपन के चमकते-दमकते वैभव के बावजूद उनकी नजरें हमेशा जमीन की ओर देखती रही। उनकी जिन्दगी और रचनाओं का सफर न केवल रोचक रहा, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी रहा।

और सुमित्रानंदन पंत के अलावा पंडित जवाहर लाल नेहरू, महादेवी वर्मा, अमरनाथ झा, हरिवंशराय बच्चन समेत और भी कई बड़े कलमकार उसी इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद के बाहर की दुनिया की बात करें तो महात्मा गांधी के उस दौर में कई बड़े दार्शनिक, कवि और शायर राष्ट्रीय फलक पर सितारे की तरह चमक रहे थे। उस कहकशां में भी फिराक की चमक कहीं कम नहीं पड़ती है।

फिराक को शायरी की प्रेरणा पिता मुंशी गोरख प्र-साद से भी मिली। बचपन के चमकते-दमकते वैभव के बावजूद उनकी नजरें हमेशा जमीन की ओर देखती रही। उनकी जिन्दगी और रचनाओं का सफर न केवल रोचक रहा, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी रहा। वे साहिर, इकबाल, फैज, तथा कैफी आजमी से अत्यधिक प्रभावित हुए। रामकृष्ण परमहंस की कहानियों से आरंभ करने के बाद उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। सन् 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए परंतु महात्मा गांधी के स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने 1918 में पद से त्यागपत्र दे दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको डेढ़ वर्ष की जेल की यात्रा सहन करनी पड़ी। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे। उनका कहना था कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है बल्कि आम भारतवासियों की भाषा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी इस सोच से अत्यधिक प्रभावित हुए, नेहरू ने फिराक को जेल से छूटने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस के कार्यालय में अन्डर सेक्रेटरी बना दिया। इंदिरा गांधी भी उनको बहुत सम्मान देती थी और उनको राज्यसभा में भेजना चाहती थी। लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने से इंकार कर दिया।

फिराक अपनी हाजिर जवाबी की वजह से फिराक काफी मशहूर थे। उनका बातचीत का लहजा इतना चुटीला होता था कि एक बार कोई उनके पास बैठ जाए तो उठता नहीं था। वह जो भी बोलते थे, बेधड़क बोलते थे और अंदाज ऐसा कि महफिल ठहाकों में भर उठती थी। वे जिन्दादिल इंसान थे तो चित्रता में मित्रता के प्रतीक थे। स्वभाव में एक औलियापन है, फक्कड़पन है और अलमस्त अंदाज है। किसी को उनका व्यक्तित्व भाया तो किसी को वह बिल्कुल पसंद नहीं आए लेकिन उनके शेरों की कद्र हर किसी ने पूरी तबीयत से की। उनका लोहा तब भी जग ने माना और आज भी मान रहा है। वे सदियों तक इसी तरह अपनी शायरी के कारण जीवंत बने रहेंगे।

फिराक की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इलहाबाद बीता। और यहीं से वे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। इलाहाबाद में फिराक, महादेवी वर्मा और निराला को मिलाकर उस दौर के साहित्य की दुनिया की त्रिवेणी बनती थी। उनकी अनौपचारिक संगोष्ठियों में अंग्रेजी के विद्वानों के साथ-साथ तुलसी, कालिदास और मीर के पाठ भी समानांतर चलते थे। उनके आवास लक्ष्मी निवास पर साहित्यकारों की खूब महफिल सजती थी। महफिल सजाने वालों में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचन्द भी शामिल थे। फिराक भरी-पूरी संभावनाओं का नाम रहा है, जहां साहित्य की अनेक सरिताएं प्रवहमान रही हैं। फिराक तबीयत से भले ही हर किसी को बागी नजर आए लेकिन उनकी शायरी सहज थी। उनके शेरों में संवेदनाएं, नेकदिली और जिंदादिली का अह-सास कोई भी कर सकता है। उर्दू गजल के पारंपरिक अंदाज में बिना किसी छेड़छाड़ के नए लहजे की शायरी की जो अद्भुत मिसाल उन्होंने पेश की, उससे शायरी के कद्रदानों के अलावा मशहूर शायर भी उनके कायल हो गए।

निदा फाजली जैसे शायर ने तो शायरी की दुनिया में गालिब और मीर के बाद फिराक को तीसरे पायदान पर रखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जैसे साहित्यकारों के सान्निध्य में उन्होंने अपनी शायरी को ऊंचाई दी। पद्मश्री अली सरदार जाफरी ने फिराक को उर्दू शायरी की नई आवाज करार दिया। जोश मलीहाबादी ने कहा कि फिराक उर्दू के उस्ताद शायरों में एक बड़े नामवर गोशे के मालिक हैं। साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. विश्वनाथ तिवारी ने फक्कड़, मूडी, गुस्सैल आदि अनेक परिचय के धनी फिराक को शायरी के दुनिया का बेताज बादशाह कहा है। यही कारण है कि मिर्जा गालिब और अमीर खुसरो की तरह ही फिराक गोरखपुरी के जीवन पर भी कई फिल्में बन चुकी हैं। एक फिर फिल्म गवर्नमेंट आफ इंडिया के फिल्म डिविजन ने भी बनाई है।

फिराक के जीवन पर कई किताबें भी लिखी गईं हैं। उनकी स्वयं की अनेक पुस्तक हैं, जिनमें प्रमुख हैं- गुल-ए-नगमा, बज्म-ए-जिंदगी, रंगे शायरी, मशअल, रूह-ए-कायनात, नग्मा-ए-साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज व कायनात, चिरागा, शोअला व साज, हजार दास्तान, हिंडोला, जुगनू, नकूश, आधी रात, परछाइया और ताराना-ए-इश्क, सत्यम शिवम सुंदरम। इसके अलावा फिराक ने एक उपन्यास ह्यसाधु और कुटियाह्ल तथा कई कहानियां भी लिखीं हैं। वे अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं- 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड, 1968 में साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मभूषण सम्मान, 1969 में गुल-ए-नगमा के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड एवं 1969 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। वे ऐसे लेखक एवं शायर हैं, जिनके जीवन की चादर पर सकारात्मकता, संवेदना एवं प्रेम के रंग बिखरे हुए है। फिराक दार्शनिक कवि-शायर हैं तो सनातन सत्य एवं जीवनमूल्यों को सहजता से उद्घाटित करने वाले जादूगर भी है। वे उर्दू नक्षत्र का ऐसा जगमगाता सितारा हैं, जिसकी रोशनी शायरी को सराबोर करती रहेगी, इस अलमस्त शायर की शायरी की गूंज हमारे दिल और दिमाग में हमेशा जिन्दा रहेगी। उनके पुण्यतिथि पर उन्हीं के शब्दों में कहें तो-

ऐ मौत आके खामोश कर गई तू,
सदियों दिलों के अन्दर हम गूंजते रहेंगे।

घूँघट की बगावत

9 मार्च 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

देश की शिक्षा व्यवस्था में समकक्षता तथा स्तरीय समानता की आवश्यकता

संसद के सदन लगातार स्थगित होते रहें और विश्वविद्यालय में कक्षाओं के नियमित चलने के उपदेश दिए जाएं, तो इसे अनावश्यक प्रलाप ही कहा जाएगा। यदि संसद सही उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगी तो नगरपालिका के पार्षद से अपेक्षा क्या बेमानी नहीं होगी? कार्यकारी पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अनुकरणीय और शालीन आचरण प्रस्तुत करना होता है। नीतियां कितनी ही सजग, सतर्क और व्यावहारिक क्यों न हों, जब वे केवल कागजों में रह जाएं, तब समझना चाहिए कि उनके क्रियान्वयन के प्रति जिम्मेदार लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया।

दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन यहां के हालिया विधानसभा चुनाव सारे देश के लिए आकर्षण और उत्सुकता का केंद्र बने रहे। विभिन्न दलों ने जिस ढंग से चुनाव प्रचार के समय एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए, जिस भाषा का उपयोग किया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हो रहे शालीनता के इस हनन का बच्चों तथा युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ध्यातव्य है कि देश के भविष्य के कर्णधारों की पीढ़ी की तैयारी केवल घरों और कक्षाओं में ही नहीं होती है, बल्कि उस पर समाज के विशिष्ट जनों के आचरण का भी प्रभाव पड़ता है। देश के चयनित प्रतिनिधियों और संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रभाव तो उन पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि सारे संचार माध्यम लगातार उनसे संबंधित वर्णन ही प्रचारित-प्रसारित करते रहते हैं। स्कूलों या महाविद्यालयों की कक्षाओं में नैतिकता, मानवीय मूल्यों की आवश्यकता पर अपने प्राध्यापक का प्रभावशाली भाषण सुनकर आया युवक जब संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखता है और पाता है कि वहां तो सब कुछ उससे विपरीत हो रहा है, जो उसे सिखाया-पढ़ाया गया है, तब उसकी वैचारिकता सही और गलत के बीच हिचकोले खाने लगती है। ऐसी स्थिति में उस पर नकारात्मकता के हावी होने की ही आशंका अधिक बनती है। वह यदि अपने कुलपति या प्राचार्य की टेबल पर चढ़कर कागज फाड़कर उनके मुंह पर फेंक देता है, तब वह किसी आधिकारिक रूप से सम्मानित घोषित महानुभाव का ही अनुसरण कर रहा होता है। जब देश का युवा भारत की संसद में असंसदीय आचरण देखता है, जब वह संसद में अध्यक्ष और सभापति का असम्मान होते देखता है, तब उससे वह अनजाने और अनकहे ही बहुत कुछ अंतर्निहित कर लेता है।

संसद के सदन लगातार स्थगित होते रहें और विश्वविद्यालय में कक्षाओं के नियमित चलने के उपदेश दिए जाएं, तो इसे अनावश्यक प्रलाप ही कहा जाएगा। यदि संसद सही उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेगी तो नगरपालिका के पार्षद से अपेक्षा क्या बेमानी नहीं होगी? कार्यकारी पीढ़ी का भावी पीढ़ी के प्रति सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व अनुकरणीय और शालीन आचरण प्रस्तुत करना होता है। नीतियां कितनी ही सजग, सतर्क और व्यावहारिक क्यों न हों, जब वे केवल कागजों में रह जाएं, तब समझना चाहिए कि उनके क्रियान्वयन के प्रति जिम्मेदार लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया।

देश में नई शिक्षा नीति चार वर्ष पहले लागू की गई थी। अब उसका तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य अपने चुनावी हित के लिए भाषा के नाम पर इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। उनका यह रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि देश की शिक्षा व्यवस्था में समकक्षता तथा स्तरीय समानता लाना परम आवश्यक है। इसमें दो राय नहीं कि सभी राज्यों के अधिकारियों और विशेषज्ञों के सहयोग से बनी नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली को भारत की संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। यह ज्ञान-सृजन में भारत की अग्रणी भागीदारी भी लक्षित करती है। इसमें ऐसी भावी पीढ़ी तैयार करने की क्षमता है, जो भारत के प्रति समर्पित होगी और उसकी ह्यविविधता में एकताह्न को साकार कर विश्व के समक्ष उदाहरण बनाकर प्रस्तुत कर सकने की सामर्थ्य से परिपूर्ण होगी।

उसमें भारतीय मूल्यों की समझ तो होगी ही, उसकी सराहना का भाव उसमें स्वतः ही अंतर्निहित हो जाएगा, लेकिन यह सब तभी संभव होगा, जब शिक्षा नीति का केवल राजनीति के कारण विरोध कर उसके क्रियान्वयन में बाधाएं उत्पन्न न की जाएं।

हर सरकार और विशेष रूप से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को यह समझना चाहिए कि उसके निर्णय भारत के युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं पर सदैव खरे उतरें। स्टालिन सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि उसका आचरण भारत की नई पीढ़ी को प्रभावित करने वाला है। जनता के विश्वास पर खरा उतरना हर सरकार का नैतिक कर्तव्य है। ऐसा करने में पक्ष या विपक्ष में होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि इस उत्तरदायित्व को अनेकानेक अवसरों पर भुला दिया जाता है।

संविधान केवल चुनावी हार-जीत तक सीमित नहीं है। उसमें व्यावहारिक शालीनता, सेवा, अनुकरणीय आचरण, ईमानदारी तथा निष्कपटता भी अंतर्निहित हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक में अध्यक्ष डा. राजेंद्र प्रसाद तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा. भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भविष्य में संविधान के प्रविधानों की सार्थकता और उपयोगिता, उसका क्रियान्वयन करने के लिए चुने गए लोगों पर यानी उनकी प्रवृत्तियों, नीयत और नैतिकता पर निर्भर करेगी। अपेक्षा तो यही थी कि स्वतंत्र भारत में नेताओं की जो नई पीढ़ियां आएंगी और सत्ता संभालेंगी वे भी उन्हीं आदर्शों का पालन करेंगी जिन पर चलकर स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा करने वाले गिनती के लोग रह गए हैं। नई शिक्षा नीति हमारी इसमें मदद कर सकती है, लेकिन तभी जब उसे अमल में लाने के लिए सभी अपना योगदान करें।

नई चुनौतियां, द्विपक्षीय वाताएं और नए मुक्त व्यापार की संभावनाएं

2044 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की डगर पर बढ़ते कदम

जहाँ अमेरिका से निर्मित टैरिफ चुनौतियों के बीच अब भारत को निर्यात के नये मौके मिलने की उम्मीद है वहीं ट्रंप की नीति से भारत को -चीन प्लस वन रूप में वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ने का मौका भी मिलते दिखाई दे सकेगा।

उल्लेख्य है कि 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वेबीनार को संबोधित करते हुए कहा था कि दुनिया का हर देश भारत के साथ आर्थिक कारोबारी साझेदारी मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत के उद्योग कारोबार प्रक्षेत्र द्वारा नए मौकों को मुट्ठी में कैद करने के लिए तत्परता के साथ बढ़ना चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ट्रंप द्वारा अपनाई जा रही अमेरिका फर्स्ट और रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति के कारण दुनिया में बहुत तेजी के साथ आर्थिक और कारोबारी उठा-पटक चल रही है। नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। वैश्विक व्यापार नए सिरे से स्थापित होने जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) अब मुख्य स्तंभ के रूप में नहीं बचा है और सबसे पसंदीदा राष्ट्र (मोस्ट फेवरेट नेशन-(एमएफएन)) के दर्जे के तहत गैर-भेदभावपूर्ण शुल्क समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में भारत ने इस नए बदलाव को समझते हुए रणनीतिपूर्वक आगामी एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले- 2025-26 के बजट में अमेरिका से आने वाली वस्तुओं जैसे महंगी मोटर साइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टालेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे कुछ सामानों पर शुल्क घटा दिए हैं। मित्र देशों के साथ भी द्विपक्षीय व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की ऐसी रणनीति पर बढ़ना शुरू कर दिया है जिसमें मित्र देशों को पर्याप्त रियायतें भी हैं।

हाल में 5 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आगामी 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ (प्रतिस्पर्धी शुल्क) लगाए जाने की घोषणा किया है। ट्रंप ने 4 मार्च से कनाडा और मैक्सिको पर 25 फीसदी चीन के आयात पर 10 फीसद, अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी किए जाने के बाद इन देशों द्वारा भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए जाने से नया ट्रेड वार शुरू हो गया है। यद्यपि ट्रंप ने भारत पर टेरिफ रेट की घोषणा नहीं की है किंतु भारत पर टैरिफ वृद्धि चीन और कनाडा से कम होगी। यह स्थिति भारत के पक्ष में है। भारत अभी अमेरिका से आयात होने वाले उत्पादों पर औसतन 9 फीसद का टैरिफ लगाता है। ऐसे में अमेरिका भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के आधार पर 9 फीसद से अधिक टैरिफ नहीं लगाएगा।

गोल्ड मैन सॉक्स के मुताबिक - अमेरिकी टैरिफ से भारत को जोडी पो पर अधिकतम 6 फीसदी का असर संगत है, जो बेहद कम है। सिटी रिसर्च के अनुसार, भारत को करीब 7 डॉलर का नुकसान हो सकता है जबकि अमेरिका के साथ व्यापार लक्ष्य पांच सौ (500) अब डॉलर सुनिश्चित हुआ है। निसंदेह टैरिफ कर का चुनौतियों के बीच भारत अमेरिका के

लिए उपयुक्त टैरिफ रियायतों की नई रणनीति के साथ द्विपक्षीय व्यापार वाताओं को भी नई रणनीति के साथ ट्रंप की टैरिफ मार से मुकाबला करने को डगर पर सुनियोजित रूप से आगे बढ़ रहा है। इस परिपेक्ष्य में - 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग (ईयू) की उर्सला बोन लेवेन ने दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के लिए मुक्त व्यापार समझौता को लेकर जारी - किंतु परंतु को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने इस बारे में प्रतिबद्धता जताते हुए अपने संबंधित पत्रालयों को निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत- व्यापार समझौते पर इस वर्ष - 2025 के अंत तक मुहर लगाई जाए। उल्लेख्य है कि विगत 1 फरवरी मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के दौरान, द्विपक्षीय कारोबार को 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार पिछले माह फरवरी में भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के व्यवसाय एवं कारोबार मंत्री जोनाथन रेनाल्ड्स ने कहा कि व्यापारिक समझौते का उद्देश्य पांच से छह वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को तीन गुना करना है। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार और निवेश समझौते को इसी साल 2025 में पूर्व किए जाने के मद्देनजर भी भारत ने रणनीति तय की है। महत्वपूर्ण बात यह कि अमेरिका यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन, तीनों का भारत के कुल द्विपक्षीय वैश्विक कारोबार का हिस्सा है। वर्ष - 2030 तक भारत इन तीनों के साथ अपने द्विपक्षीय कारोबार को कम से कम तीन गुना बढ़ाने की डगर पर आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से उस समय ट्रंप के टैरिफ तुफान के बीच प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय व्यापार वाताओं ऐसी डगर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। जो उन्होंने पिछले वर्ष अपने तीसरे कार्यकाल से हो लगातार आगे बढ़ाना शुरू किया है। पिछले वर्ष से ही इस रणनीति से द्विपक्षीय व्यापार के अच्छे अध्याय लिखे जा रहे हैं। इन सबके साथ जिस तरह ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के साथ, अमेरिका को तेजी से आर्थिक मजबूती देने का प्रयास कर रहे है। उसी तरह भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी इंडिया कटे की रणनीति को तेजी से बढ़ा करके घरेलू उद्योग - कारोबार को और अर्थव्यवस्था को बेरोकटोक आगे बढ़ाने के मौके मुट्ठी में ले सकते हैं।

उम्मीद है कि - अमेरिका द्वारा आगामी दो अप्रैल से भारत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाने की नई चुनौतियों के भारतीय नीति - निमार्ताओं द्वारा ट्रंप प्रशासन की नीतियों से भारत पर होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों का सतत मुल्यांकन करते हुए रणनीति का रुप से द्विपक्षीय कारोबार की डगर पर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ सरकार अमेरिकी टैरिफ की नई चुनौतियों के बीच नई द्विपक्षीय वाताओं एवं मुक्त व्यापार समझौतों की डगर तेजी से बढ़ेगी और अमेरिका सहित दुनिया के कोने कोने के देशों में कारोबार की नई संभावनाओं को मुट्ठियों में लेते हुए 2044 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की डगर पर तेजी से बढ़ने में सफल होगी।

बचपन का खेल

कुदरत पर इंसानी कहर

आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने अप्रैल से लेकर अगस्त-2024 के मध्य आए मरीजों के आंकड़ों के अध्ययनोपरान्त पाया कि 39 दिन तापमान 40 डिग्री के ऊपर था। जो सामान्य से कहीं अधिक है। एम्स के ये आंकड़े बताते हैं कि - 2021 में गोरखपुर और उसके आस पास के क्षेत्रों में 40 डिग्री या उससे अधिक तापमान वाले महज छः दिन थे। तीन साल में छह गुना से अधिक यह बढ़ोत्तरी क्या कहती है? यह प्रश्न तब और काबिले गौर हो उठता है, जब हम उस भविष्यवाणी पर विचार करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि- पिछले वर्ष से कहीं अधिक गर्म यह वर्ष हो सकता है।

एक अन्य शोध में पाया गया है कि भारत में सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के मरीजों की आमद अब फरवरी से ही शुरू हो गई है। कुछ साल पहले ऐसे रोगी मई जून में डाक्टरों का दरवाजा खटखटाते थे। मैं यहां पर नई दिल्ली की एक बेहद चिंताजनक रिपोर्ट चिंतन मनन करना चाहता हूँ। वहां के चिकित्सकों के अनुसार, 40 से अधिक बच्चे एक दुर्लभ बीमारी - जेरोडर्मा पिग्मेंटोसा से पीड़ित हैं। यह इतना खतरनाक रोग है कि अगर धूप की महज एक किरण उनके शरीर पर पड़ जाए, तो उन्हें कैंसर हो सकता है। इन बच्चों को सिर से पांव तक ढँककर रखा जाता है। वे रात में ही घर से बाहर कदम रख पाते हैं। क्या आपको भी सर्दियाँ सिकुड़ती और उनकी जगह गर्म दिन पसरते नजर आ रहे हैं। इसे मौसम की दगाबाजी कहा जाए या फिर कुदरत पर इंसानी कहर का नतीजा? इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यह भी जानना जरूरी है।

गोरखपुर एम्स के चिकित्सक अचंभित हैं। उनके यहां हाइड्रो वैक्सीन फार्म के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह त्वचा रोग है। जो तेज धूप के संपर्क में आने से होता है आमतौर पर यह रोग और मरीज रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गोरखपुर और इसके आस पास का क्षेत्र तराई जैसा है यहां धूप और शुष्कता कम रहती है। मतलब साफ है धूप की प्रखरता इतनी बढ़ रही है कि मनुष्य की चमड़ी उसे सहन नहीं कर पा रही है।

नई उभर की नई फसल के लिए इससे घातक और क्या हो सकता है। इस गर्म होते वातावरण में मच्छर जनित बीमारियां भी नए रिकार्ड गढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट बताती है कि पिछले 60 वर्षों में डेंगू फैलाने वाले अन्दर के संक्रमण में 43.3 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2023 में तो डेंगू के मामलों ने एक नया विश्व रेकार्ड तैयार किया है। इस वर्ष पचास लाख से अधिक लोग मच्छरों से पीड़ित अस्पतालों तक पहुंचे। गर्मी किस तरह से जानलेवा होगी है इसका पता ग्लोलबल क्लाइमेट एण्ड हेल्थ एलाएन्स की कार्यकारिणी जेनीमिलर के इस बयान पर गौर फरमाएं। मिलर ने पिछले वर्ष कहा था कि - अत्यधिक गर्मी के कारण सिर्फ भारत में सिर्फ भारत में 40 हजार से अधिक स्ट्रोक सामने आए हैं। इनमें से 700 लोगो ने दम तोड़ दिया।

गोरखपुर एम्स के चिकित्सक अचंभित हैं। उनके यहां हाइड्रो वैक्सीन फार्म के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह त्वचा रोग है। जो तेज धूप के संपर्क में आने से होता है आमतौर पर यह रोग और मरीज रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गोरखपुर और इसके आस पास का क्षेत्र तराई जैसा है यहां धूप और शुष्कता कम रहती है। मतलब साफ है धूप की प्रखरता इतनी बढ़ रही है कि मनुष्य की चमड़ी उसे सहन नहीं कर पा रही है।

लेसेंट काउंट डाउन से जुड़े विशेषज्ञ मानव शरीर पर जलवायु परिवर्तन के कारण दुष्प्रभावों का भी अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने जिन पहलुओं को अपने शोध का हिस्सा बनाया उनमें 10 के हालात चिंताजनक है।

सुनिश्चित है आगामी दिन अ-शुभ गाथाओं को संजोते देखे जा सकते हैं। मौसम के छलिएपन की एक दास्तान यह भी है- 23 दिसंबर की हर्षिल घाटी में आसमान से जैसे रुई के फाहे बरस रहे हों। वह बर्फ थी जो 10 घंटों तक गिरती रही। देखते ही देखते सड़कें सफेद चादर से ढक गईं। और यातायात को रोकना पड़ा। मौसम का ऐसा नजारा देख कर यात्री खुशी से उछल पड़े। अनुमान लगाते कि इस साल बर्फ ज्यादा गिरेगी। ये खुशफहमी साबित हुई। गुजरती सर्दी अकल्पनीयतौर पर गर्म साबित होने लगी। गत 26 जनवरी को नई दिल्ली में तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जबकि दिल्ली और भारत के मैदानों में ये दिन भयंकर ठंड के और कोहरे से सराबोर होते हैं। राजधानी से दूर बेंगलुरु में भी ऐसे ही हैरानी भरे समाचार पढ़ने सुनने को मिलते रहे हैं। इस मनोरम शहर में तापमान फरवरी के महीने में ही 38 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कई मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार बेंगलुरु में गर्मी दिल्ली से भी ज्यादा पड़ सकती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में फरवरी में गर्मी से बेजार होती रही है। वहां तापमान 38.7 डिग्री तक पहुंच गया और हवाओं ने गर्मी पकड़ ली। मौसम की मार धरती के सागरों और महासागरों को भी नुकसान पहुंचा रही है। समूची दुनिया में समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। आशंका है कि मुंबई कराची ढाका सहित तमाम शहर कुछ दशकों में जलमग्न विषय बन जाएगा। स्मरणीय हो कि दुनिया की लगभग दस फीसदी आबादी उच्च ज्वार रेखा से पाँच मीटर से भी कम ऊंचाई वाले तटीय क्षेत्रों में रहती है।

ऊंचे लोग ऊंची पसंदः सुपरफूड मखान

आज भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि - 21वीं सदी भारत की है। और 2017 तक हमारा भारत एक विकसित देश बन जायेगा परन्तु आज की स्थिति तो यही है कि हमारे देश में जन संख्या के एक बड़े हिस्से के पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है है। वर्ष-2024 के ही एक सर्वेक्षण के अनुसार भूखमरी इंडेक्स में दुनिया के 127 देशों में हमारा स्थान 105वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि - भले ही हम यह दावा कर लें कि हमारा भारत जल्द ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। पर यह वास्तविकता है कि - अभी हम भूख मिटाने लायक भी नहीं बन पाए हैं। हमारा देश विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र राष्ट्र बन जाए, यह कौन नहीं - चाहेगा पर हमें यह भी चाहना होगा कि वह दिन शीघ्र आए जब देश की आम जनता भी मखाना जैसा महंगा खाद्य खा सके। मखाने का स्वाद उसे भी पता हो। अभी तो यह बात एक खुशफहमी ही लगती है। हमें इस बात को भी नही भूलना होगा कि-वर्ष-2025 की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार- हमारे देश के 28 राज्यों में बच्चे कुपोषण के शिकार है। महिलाओं की स्थिति तो इन बच्चों से बुरी है।

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे में यह देखने को मिला है कि 15-20 साल की लड़कियों, महिलाओं की आधी से जादा आबादी रक्ताल्पता जैसे रोग पीड़ित है। 21 प्रतिशत पुरुष भी खून की कमी (एनिमिया) के शिकार हैं।

सवाल अमीरी-गरीबी का नहीं सवाल तो समस्या की तह तक पहुंचकर उचित समाधान को तलाशने का है। सुपर फुड को दुनिया के बाजारों में पहुंचाकर बिहार के किसानों की बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाना कतई गलत नहीं है। देश में उत्पन्न होने वाले मखाने में से 35 प्रतिशत बिहार में होता है। इसका अर्थ यह है कि मखाना-बाजार से होने वाले लाभ ड्ड में बिहार के किसान का हिस्सा अच्छा खासा होगा। यह स्थिति स्वागत योग्य है। यह बात भी मन में कहीं न कहीं आ सकती है कि देश का आम नागरिक बाब

इतना महंगा सुपर फूड प्रधानमंत्री या उनका मित्र परिवार पूरे साल खा सकता है। जिस देश में 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज देकर पेट भरवाना पड़ रहा हो वहां का आम आदमी इतना मंहगा सुपर फुड कैसे खा सकता है....।

मखाने का स्वाद चख पायेगा। नेतृत्व का बोला गया हर शब्द महत्वपूर्ण होता है। अपेक्षित है कि है कि नेतृत्व द्वारा (चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष) बोला जाने वाल हर शब्द बोल कर बोला गया है। उम्मीद जगाना अच्छी बात है जरुरी भी है पर उम्मीद भी बेबुनियाद नहीं होनी चाहिए। पिछले साठ-सत्तर साल में देश में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर गर्व किया जा सकता है। पर यह बहुत कुछ पर्याप्त बहुत नहीं है। और अभी बहुत कुछ करना है हमें। आज हम जहाँ है वहां पहुंचने का श्रेय राह में उठाये गये हर कदम को है। पहला कदम जब उठता है तो मंजिल एक कदम नजदीक आती है।

कहते हैं राजनीति की दुनिया में कुछ भी कहा जा सकता है। इस दुनिया के हर एक प्राणी का यह विशेषाधिकार मिला हुआ है कि वह जो चाहे बोले जो चाहे दावे करे। खासकर चुनावों के मौकों पर तो कुछ भी कहने दावा करने का यह अधिकार खूब काम में लिया जाता है। इस बात को विशेषता यह भी है कि राजनेताओं के कथनों दावों की सत्यता की कोई शिनाख्त नही होती। जो नेता बोले सो सच। होता यह भी है नेता इन दावों-बातों को अक्सर भूल जाते हैं। कहना जान बूझ कर भुला दिया जाता है।

फिर अगला चुनाव आ जाता है। फिर नए दावे-नई बातें। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक चुनाव में' एक नेता जो बोलता है, जैसे ही कुछ दूसरे चुनाव में दूसरा नेता बोल जोता है। मजेदार बात यह है कि राजनीति की एक जरूरत के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह सारी बाते आज याद आ रही हैं उनका रिश्ता मखाना से है। वैसे यह रिश्ता नायाब चीज से हो सकता है, पर फिलहाल यह सब मखाने के संदर्भ में याद आ रहा है। सब जानते हैं कि मखाने बहुत पौष्टिक होते हैं। सामान्यतः बड़े लोग या धनिक लोग ही इसका सेवन कर पाते हैं।वैसे अक्सर उपवास आदि में ही मखाने ज्यादा खाये जाते हैं।

ज्ञातव्य है कि - मखाने मुख्य भोजन नहीं होते, नाश्ते या नमकीन के रूप में हो इनका उपयोग हो पाता है। ऐसा इसलिए कि मखाना एक महंगा पदार्थ है। कहा जाता है कि बाजार में इसका भाव 1500 से दो हजार रुपये प्रति कि किलो है। थोक भाव कुछ कम होता होगा। जैसा कि सब जानते हैं, कि यह बहुत महंगा और बहुत पौष्टिक आहार है। हमारे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री को यह आहार बहुत पसंद है। हाल ही में जब वह आगामी चुनावों के संदर्भों हमें प्रचार करने के लिए बिहार गाए थे तो वहां एक विराट जनसभा में उन्होंने बताया था कि वे साल के 365 दिनों में से 300 दिन तो वह मखाना ही खाते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य का एक कारण यह आहार भी हो सकता है। उस सभा में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दुनिया के बाजार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। हमारे देश में बिहार राज्य में इसकी सर्वाधिक पैदावार है। देश में मखाने की उपज का लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा बिहार में होता है। कहा जाता है - 25-30 हजार किसान परिवार उस खेती से जुड़े हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com